

नेपाल में जलप्रलय: बाढ़ से भारी तबाही, 157 लोगों की मौत, 133 भारतीयों समेत 500 से ज्यादा लापता

एजेंसी
काठमांडू: पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल के कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस जलप्रलय में अब तक 157 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 500 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में 133 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जिससे भारत में भी चिंता की लहर दौड़ गई है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, चितवन और गोरखा जिलों में देखने को मिला है, जहां पानी के तेज बहाव ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस-नहस कर दिया है।

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लापता 133 भारतीयों में बड़ी संख्या उन तीर्थयात्रियों की है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे। इसके अलावा कई विदेशी पर्यटक और स्थानीय नागरिक भी लापता हैं। जलप्रलय की चपेट में आकर नेपाल के विभिन्न इलाकों में तैनात करीब 80 सुरक्षाकर्मी



नेपाल के भोटेकोशी की बाढ़ में 40 किमी सड़क और 22 पुल बहे

काठमांडू: रसुवा की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ ने रसुवागढ़ी से लेकर धादिङ के गल्छी तक बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस इलाके में 40 किमी की पक्की सड़क बाढ़ की चपेट में आ गई है। इसी तरह बाढ़ में 22 पक्के पुल और पांच बेलीब्रिज बह गए हैं। सड़क विभाग के प्रवक्ता एवं उपमहानिदेशक शुभराज न्यौपाने के अनुसार, रसुवा, नुवाकोट और धादिङ के विभिन्न क्षेत्रों में 22 पक्के पुल तथा पांच बेलीब्रिज बाढ़ में बह गए हैं। उन्होंने बताया कि त्रिशूली, बेरावती, तादी खोला और गल्छी समेत विभिन्न स्थानों पर बने पक्के पुल बाढ़ की चपेट में आए हैं। बाढ़ से नुवाकोट के बेरावती से रसुवागढ़ी सीमा नाके को जोड़ने वाली सड़क को भी भारी नुकसान पहुंचा है। न्यौपाने के अनुसार, बेरावती से रसुवागढ़ी नाके तक करीब 40 किलोमीटर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की प्रारंभिक जानकारी मिली है। इस मार्ग के विभिन्न स्थानों पर स्थित पक्के पुल भी बाढ़ में बह गए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रारंभिक क्षति का विवरण है और नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है।

और पनबिजली परियोजनाओं में काम करने वाले कई कर्मचारी भी संपर्क से बाहर हो गए हैं। अचानक आई इस बाढ़ का कारण फिलहाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि तिब्बत क्षेत्र में आए भूकंप, भारी हिमस्खलन या किसी ग्लेशियर झील के फटने की वजह से नदी के जलस्तर में यह

विकराल वृद्धि हुई है। इस भयंकर तबाही ने नेपाल के बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। रसुवागढ़ी बॉर्डर के पास बाढ़ ने कई घरों, लगभग 19 मोटरबल पुलों और सड़कों को पूरी तरह से बहा दिया है। इसके चलते नेपाल की एक दर्जन से अधिक पनबिजली परियोजनाओं (हाइड्रोपावर

प्रोजेक्ट्स) का काम ठप हो गया है और कई प्रोजेक्ट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और स्थानीय पुलिस ने बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। सेना ने प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 15 से अधिक



नेपाल में भीषण आपदा पर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का संदेश- यह समय बेहद संवेदनशील

काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने रसुवा की भोटेकोशी नदी में बुधवार सुबह आई भीषण बाढ़ से हुई भारी जन-धन की क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाढ़ में अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत की दुखद खबर मिली है। उन्होंने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बाढ़ की खबर मिलते ही सरकार ने बिना देर किए अपने सभी उपलब्ध संसाधनों और तंत्रों को बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान में लगा दिया। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक के बाद राष्ट्रीय परिषद और मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई, जिसमें बचाव, खोज और राहत कार्यों को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, हालांकि खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट की घड़ी में भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों और अन्य

प्रभावित लोगों के बचाव के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेलपलाइन नंबर जारी किए हैं और नेपाल सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए भारतीय

नेपाल में अचानक आई बाढ़ से तबाही पर राष्ट्रपति मुर्मु और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने जताया दुख

नई दिल्ली। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई भारी तबाही और जनहानि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को गहरा दुख व्यक्त किया है। दोनों नेताओं ने इस कठिन समय में नेपाल के लोगों के प्रति एकजुटता जताते हुए प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया मंच हाएक्सब्लू पर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाल की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में नेपाल के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। भारत नेपाल सरकार के राहत और बचाव प्रयासों में प्रभावित लोगों की मदद के लिए हरसंभव सहयोग देने को तैयार है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने भी नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने लापता लोगों के सुरक्षित और शीघ्र बचाव के लिए भी प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन घड़ी में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल की जनता के साथ हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से की बात, बाढ़ में जनहानि पर जताया दुख

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की और नेपाल में बाढ़ के कारण हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस मुश्किल समय में नेपाल के लोगों के साथ भारत की एकजुटता व्यक्त करते हुए हर संभव मानवीय और राहत सहायता उपलब्ध कराने का भारोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच हाएक्सब्लू पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर नेपाल में बाढ़ के कारण हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में भारत की जनता नेपाल के अपने भाई-बहनों के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि बचाव और राहत कार्यों के लिए भारतीय दल नेपाल के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।

नागरिक +977 9851316807 और +977 9709107500 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही, गंडक नदी के उफान पर होने के कारण भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

संक्षिप्त खबरें

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में गहरी खाई में गिरी वैन, 6 लोगों की मौत

राजौरी। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के शिंदरा इलाके में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक ईको वाहन पुंछ से शिंदरा की ओर जा रहा था। शिंदरा क्षेत्र में पहुंचने के दौरान वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गया और गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रशासन और संबंधित विभागों को सूचना दिए जाने के बाद बचाव दल भी मौके पर पहुंचे। खाई में गिरे वाहन से घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हादसे के कारण क्षेत्र में काफी देर तक मातम का माहौल बना रहा। जिला प्रशासन के अनुसार, वाहन पुंछ से शिंदरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान शिंदरा क्षेत्र में चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ईको सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि छह लोगों ने मौके पर ही हम टोड़ दिया। तीन अन्य लोग घायल हुए, जिन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान 30 वर्षीय जुल्फत भी पत्नी मुहम्मद अमीन, 19 वर्षीय मसरत नाज, पत्नी अजकर अहमद, 20 वर्षीय मुहम्मद फरीद पुत्र मुहम्मद राशिद, 32 वर्षीय मुहम्मद शफीक पुत्र मुहम्मद शफी, 32 वर्षीय नजाकत हुसैन पुत्र मुहम्मद शरीफ और 23 वर्षीय जहूर अहमद, पुत्र शमस दीन के रूप में हुई है। सभी मृतक पुंछ जिले के सेरी चोहाना गांव के रहने वाले बताए गए हैं।

ईद मिलाद-उन-नबी पर रांची में धूमधाम से निकला जुलूस

बिभा संवाददाता
रांची। ईद मिलाद-उन-नबी पर बुधवार को धूमधाम से रांची में जुलूस निकाला गया। एदार ए शरीया झारखंड की देखरेख में, सुन्नी बेलवी सेंट्रल कमिटी की ओर से और उलेमा के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। हिंदपीढ़ी, नाला रोड, खेत मोहल्ला, गोवाला टोली, गोदरी कुनेशी मोहल्ला, आजाद बस्ती, थडूपकना, मोरहाबादी, कांटा टोली, मौलाना आजाद कॉलोनी, गौस नगर, इलाही बख्श कॉलोनी, नेवरी सीरत नगर, बरियातु, भिट्टा, कांके, बारूह, आजाद हिंद नगर, डोरंडा, रहमत कॉलोनी, मनी टोला, गौस नगर, दर्जी मोहल्ला, फिरोदस नगर सहित अन्य जगहों से जुलूस अपने-अपने तय रास्ते से होते हुए सुबह 11 बजे कर्बला चौक पहुंचे, जहां से मौलाना मुहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी, मौलाना डॉ तालुद्दीन रिजवी, मौलाना मसूद



फरीदी, कारी अयूब रिजवी, मुफ्ती आकिब जावेद, अकीलुर रहमान, मो इसलाम, मो आफताब, परवेज ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस विक्रांत चौक, टैक्सो स्टैंड, डेली मार्केट, उर्दू लाइब्रेरी, अंजुमन इस्लामिया होते हुए एकरा मस्जिद के पास रतन टॉकीज में सभा स्थल में तब्दील हो गया, जहां पर सभा जलसा को सम्बोधित करते हुए एदार ए शरीया

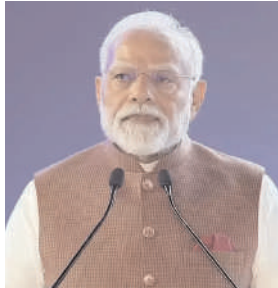
झारखंड के नाजिमे आला ने कहा कि मिलादे मुस्तफा माना और योमे विलादत हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि और सल्लम का जन्म दिवस ईद मौला दुनबी के मौके से बड़ी धूमधाम से जुलुसे मुहम्मदी निकालना बरकत का जरिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों के लिए अल्लाह तआला की तरफ से सबसे बड़ी बरकत व नेमत यह है कि

अल्लाह ने हजरत मुहम्मद मुस्तफा को इस दुनिया में भेजा। जिसके बारे में रब ने कहा कि नेमत और फजल के मिलने पर जश्न मनाओ, आज हमें पैगंबर की शिक्षाओं पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। सभा को संबोधित करते हुए मौलाना डॉ तालुद्दीन ने कहा कि पैगंबर के आगमन के दिन को बड़े सम्मान के साथ मनाया सभी सहाबा की सुन्नत है और पैगंबर ने खुद अपनी मौलाद मनाई थी। हर साल खूब धुम धाम से जश्ने ईद मौलादुननबी मनाया इसलाम और मानवता का हिस्सा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि हजरत मुहम्मद सबके लिए हैं। हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। शमशेर आलम वाइस चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कि पैगंबर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। सेक्रेटरी अकील रहमान,

मुहम्मद इस्लाम, महबूब हुसैन रिजवी, मेहताब आलम, परवेज अख्तर, जमील गद्दी, भारतीय एकता कमिटी के युवाओं और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी जुलूस में व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। जय सिंह यादव, सागर कुमार, मौलाना तहजीब-उल-हसन रिजवी और अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया। सभा की समाप्ति के बाद जुलूस रतन टॉकीज मेन रोड, जीईएल चर्च, रोसपा टावर, सुजाता चौक, ओवर ब्रिज, राजेंद्र चौक, पुराना झारखंड उच्च न्यायालय होते हुए रिसालदार उस मैदान पहुंचा, जहां अंतिम सभा जलसा में बदल गया। जुलूस के दौरान रांची जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती की गई थी।

प्रधानमंत्री आज खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं को करेंगे संबोधित, पांच विषयों पर होगा राष्ट्रीय संवाद

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में देशभर के युवाओं की भागीदारी होगी और इसमें खेल, युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, वॉलंटियरिंग, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच पर लाया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि यह आयोजन मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर किया जा रहा है। देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के दो कॉलेजों से युवा इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का यह संवाद फिट, अनुशासित और खेल भावना से युक्त राष्ट्र निर्माण की उनकी दृष्टि के अनुरूप है, जिसमें युवाओं की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के केंद्र में रखा गया है।



होगा। इसमें युवाओं को प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों और पदक विजेताओं से सीधे बातचीत का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण युवा संवाद होगा, जिसमें प्रतिभागी अपने विचार और आकांक्षाएं साझा करेंगे। यह संवाद पांच प्रमुख विषयों खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर सुविधाओं और कोचिंग से मजबूत करना, 2036 ओलिंपिक के लिए प्रतिभा पहचान और दीर्घकालिक एथलीट विकास, शासन मंचों और वॉलंटियरिंग से युवा नेतृत्व तैयार करना, नागरिक जिम्मेदारी और भविष्य के कौशल से विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना तथा खेल और साधियों के नेटवर्क से नशा मुक्त युवा आंदोलन को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा।

मानसून में बड़े एवाएन1 के मामले, आईएमए ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं

एजेंसी
नई दिल्ली। मानसून के दौरान देश में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है लेकिन यह भी कहा है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। बुधवार को जारी परामर्श में आईएमए ने कहा कि एच1एन1 के अधिकांश संक्रमण हल्के होते हैं और कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि, संक्रमण के लक्षणों पर नजर रखना जरूरी है। आईएमए की एडवाइजरी के अनुसार एच1एन1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द, थकान, सिरदर्द और नाक बहने या



बंद होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों में इसके साथ मतली, उल्टी या दस्त की समस्या भी अपेक्षाकृत अधिक देखी जा सकती है। आईएमए ने लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक लेने से बचने की सलाह दी है। डॉक्टरों के मुताबिक एच1एन1 वायरल संक्रमण है, इसलिए एंटीबायोटिक्स वायरस को खत्म नहीं करती। सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, हॉट नीले पड़ना, खून वाली खांसी, अत्यधिक सुस्ती या लगातार उल्टी जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देने पर

तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी गई है। आईएमए ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने और लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। इसके साथ आईएमए ने लोगों से अपील की है कि वे हाथों की सफाई रखें, खांसते-छींकते समय मुंह ढकें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें और बीमार होने पर घर पर रहें। इस बीच दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में राजधानी में 2308 मामले सामने आए हैं। वहीं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, फिलहाल सामने आए वायरस मौसमी स्वाइन फ्लू है और इसमें किसी नए खतरनाक म्यूटेशन की पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है।



बिभा संवाददाता
रांची, 26 अगस्त (हि.स.)। रक्षाबंधन से पहले झारखंड सरकार की ओर से बहनों को उपहार दिया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 03 लाख 95 हजार 692 लाभुकों के बैंक खातों में माह अगस्त 2026 की सम्मान राशि (2,500 प्रत्येक लाभुक) का आधार बेस्ड डायरेक्ट बेंचिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया गया है। योजना के तहत लाभुकों के खातों में कुल 98 करोड़ 92 लाख 30 हजार की राशि हस्तांतरित की गई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजन्त्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना राज्य की

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। रांची जिले में योजना का लाभ पात्र लाभुकों तक पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी पात्र महिला को योजना के लाभ से वंचित न रहना

पड़े। लाभुकों के भुगतान की प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जा रही है और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यह योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है।

प्रखंड व शहरी क्षेत्रवार लाभुकों की संख्या

अनगड़ा - 16,796, अरगोड़ा शहरी क्षेत्र - 13,406, बड़ो - 20,620, बुंदू - 8,591, बुंदू नगर पंचायत - 3,566, बुंदू - 17,841, वाहो - 19,374, हेहल शहरी क्षेत्र - 16,376, कांके - 31,620, कांके शहरी क्षेत्र - 1,290, खलारी - 9,632, लापुंग - 11,866, मांडर - 23,008, नागड़ी - 18,345, नागड़ी शहरी क्षेत्र - 8,244, नामकुम - 18,071, नामकुम शहरी क्षेत्र - 9,571, ओरमाड़ी - 17,898, राहे - 9,551, रातू - 20,427, सिल्ली - 21,335, सोनाहातू - 13,114, तमाड़ - 18,832, टाउन अर्बन - 26,042, डटकी - 10152, बड़गाई शहरी क्षेत्र - 10124.

लैम्प्स में किसानों को सरकारी दर पर मिलेगा यूरिया : संजीव सरदार

बिभा संवाददाता
जमशेदपुर। पोटका लैम्प्स परिसर में किसानों के बीच यूरिया खाद वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन पोटका विधायक संजीव सरदार ने किया। विधायक ने किसानों के बीच यूरिया खाद वितरित कर कार्यक्रम की शुरूआत की। पोटका लैम्प्स के माध्यम से प्रखंड के किसानों को सरकारी निर्धारित दर 366 रुपये प्रति बोरी की दर से यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि खेती के



महत्वपूर्ण मौसम में किसानों को खाद की उपलब्धता को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसानों की

सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी जरूरत के समय उचित दर पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विधायक ने संबंधित अधिकारियों एवं लैम्प्स प्रबंधन को निर्देश दिया कि किसानों को निर्धारित सरकारी दर पर ही यूरिया उपलब्ध कराया जाए तथा वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुचारु रखा जाए, ताकि किसी किसान को अनावश्यक परेशानी न हो। यूरिया वितरण शुरू होने से क्षेत्र

के किसानों में राहत का माहौल है। किसानों ने कहा कि खेती के मौसम में समय पर खाद उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। लैम्प्स के माध्यम से सरकारी दर पर यूरिया मिलने से उन्हें बाजार की ऊंची कीमतों से राहत मिलेगी। कार्यक्रम में समाजसेवी आनंद दास, लैम्प्स अध्यक्ष पंचानन सरदार, सचिव उत्तम कुमार साहू, एकलव्य मदीना, संदीप कुमार पटबन्धा, बबलू मदीना, ग्रामप्रधान निपेन मंडल, पंचानन मंडल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

किताडीह में ईद मिलादुन्न नबी के मौके पर शामिल हुए संजीव सरदार



बिभा संवाददाता
जमशेदपुर। पोटका विधानसभा क्षेत्र के जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत किताडीह में बादशाह गुप की ओर से मोहब्बत, रहमत, शफकत और ईसाफ का संदेश देने वाले हजरत मुहम्मद की पैदाइश-ए-मुबारक के अवसर पर लंगर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोटका विधायक संजीव सरदार बतौर अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि हजरत मुहम्मद साहब का पूरा जीवन ईसानियत, मोहब्बत, रहमत, शफकत और ईसाफ का संदेश देता है। उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भाव को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन लोगों को एक-दूसरे के करीब लाने और सामाजिक एकता को मजबूत करने का काम करते हैं। विधायक ने आयोजन के लिए बादशाह गुप के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किताडीह और जमशेदपुर की पहचान हमेशा से आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की रही है। सभी धर्म और समुदाय के लोगों को मिल-जुलकर समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। लंगर में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और आयोजन की सराहना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान आपसी भाईचारे और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव, समाजसेवी राजकुमार सिंह, झामुमो नेता शेरू खान, निजाम खान सहित कई गणमान्य लोग एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

माकपा सह किसान नेता सुचांद महतो की 6वीं पुण्यतिथि, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

सिल्ली(बिभा) : झारखंड राज्य किसान सभा एवं माकपा के तत्वावधान में किसान नेता सुचांद महतो का 6 वीं स्मृति दिवस रघुनाथपुर में सम्मान पूर्वक मनाया गया। कामरेड सुचांद महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य सह झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव सुफल महतो ने सुचांद महतो के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा सुचांद महतो अंधविश्वास,डायन प्रथा, शोषण,जुल्म, अन्याय,अत्याचार के खिलाफ किसान,मजदूर, छात्र - युवाओं के संघर्ष के अथक योद्धा थे। दिल्ली किसान आन्दोलन के दौरान सरायकेला-खरसावां जिले में किसान आन्दोलन का बहू-चढ़ कर नेतृत्व किया था, उनके द्वारा चाडिल विस्थापन,तिरूलडीह गोलीकांड,जबरन जमीन अधिग्रहण जैसे छोटे बड़े दर्जनों आन्दोलन को सदैव याद रखा जाएगा। माकपा के मर्नीद गोप ने कहा सुचांद महतो लोकतंत्र,सविधान व सम्प्रदायिक सद्भाव के पक्के हिमायती थे। इसके अलावे सुरेन्द्र नाथ महतो, हरे कृष्ण महतो,शिवप्रसाद पाण्डेय,कमल पारित,सतयरंजन कोटका,तारापदो रवानी, किसान नेता निलकंठ सिंह मुंडा, यमुना देवी, प्रबोध महतो, शक्ति पर्वो मंडल, उमापदो महतो,रामाशंकर गोरई, निशिकांत महतो,परशुराम सिंह मुंडा,गुणाधर केवरात,राजेश महतो, चिंता मनी महतो, वैद्यनाथ महतो, महेंद्र महतो, कृष्ण दास महतो,अनिला भासंती महतो,लक्ष्मी महतो, सरस्वती महतो,निशा महतो आदि उपस्थित थे।

आस्था के साथ ही पर्यटन के दृष्टिकोण से भी कमड़े आश्रम का विकास जरूरी : सेठ



रांची(बिभा)। केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि न केवल श्रद्धा और आस्था बल्कि पर्यटन की दृष्टिकोण से भी कमड़े बाबा आश्रम का विकास बहुत अधिक आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसे दिव्य स्थान पर कमड़े बाबा से जुड़ी हुई सभी यादें, उनके ऊपर जमा ऋद्र विश्वास और उनकी आध्यात्मिक शक्ति न केवल आस्थावान श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करती है बल्कि इसके कारण जीवन में नई दृष्टि भी मिलती है। कमड़े बाबा आश्रम की चहारदीवारी के शिलान्यास समारोह में पूजन के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोष की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और न सिर्फ रांची बल्कि झारखंड के सभी आध्यात्मिक आस्था के केन्द्र और पर्यटन केन्द्रों का विकास एवं उत्थनन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन यह बात अफसोस की बात है कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र के पास समय पर ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा जाता है। इसका नतीजा आधिकारिक रूप से केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय से न तो वैसी योजनाओं की स्वीकृति मिल पाती है और न ही उसके लिए राशि ही प्राप्त हो पाती है। इस मामले में उन्होंने टैगोर हिल के विकास का संदर्भ देते हुए कहा कि तब चार साल पहले राज्य की तत्कालीन पर्यटन सचिव से उन्होंने स्वयं बारंबार अनुरोध किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ और अंततः किसी दूसरे मद से राशि प्राप्त कर टैगोर झील का अपेक्षित विकास हुआ। सेठ ने कमड़े बाबा आश्रम ट्रस्ट के साथ ही प्रमुख सदस्य मनोज प्रसाद से अनुरोध किया कि वे इस संदर्भ में विस्तृत योजना तैयार करने की जिम्मेदारी निजी स्तर पर लें और उसे कार्य रूप में परिणत करने और अपेक्षित योगदान देने में उन्हें खुशी होगी। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वे बरसों से इस आश्रम के विविध समारोहों में शामिल होते रहे हैं और आज इस बात की हार्दिक खुशी है कि इस आश्रम के विकास के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहा हैं। रांची की मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक स्थल न सिर्फ रांची या झारखंड बल्कि देश की भी पहचान है। अपने वक्तव्य में कमड़े बाबा आश्रम ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार मनोज प्रसाद ने कहा कि आश्रम के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं आईं लेकिन बाबा के आशीर्वाद से वह सभी दूर हो गईं। कार्यक्रम में कमड़े बाबा आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, सचिव बिपिन नाथ, सदस्य बसंत जालान, राजेश कुमार, अमित रंजन प्रसाद, मनोज प्रसाद, पवन कुमार भट्ट, सुशीव सिंह सहित अन्य मौजूद थे।

जुलूस-ए-मोहम्मदी में उमड़ा आस्था का लैलाव, उलमा ने पैगंबर-ए-इस्लाम की छीरत और शिक्षाओं का दिया संदेश

बिभा संवाददाता
बेड़ो। ईद मिलादुन्नी के मुबारक अवसर पर बुधवार को बेड़ो प्रखंड क्षेत्र के दिधिया, महरो घाघरा, नरकोपी, बिल्टी, भोगला टोली और मसयातू सहित विभिन्न इलाकों में अकीदत और उत्साह के साथ जश्न-ए-ईद मिलादुन्नी मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में जुलूस-ए-मोहम्मदी में शामिल होकर पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद मुस्तफा की पैदाइश के दिन की खुशी मनाई। सुबह से ही लोग काफिलों के रूप में मस्जिदों में पहुंचने लगे। इसके बाद अकीदमर्दों की मौजूदगी में जश्न-ए-ईद मिलादुन्नी के



जुलूस का आगाज हुआ। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में परचम लेकर शामिल हुए। रास्ते भर नातिया कलाम पढ़े गए और पैगंबर-ए-इस्लाम की शान में नारे लगाए गए। जगह-जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत करते हुए फूल बरसाए और मिठाइयां बांटीं। जुलूस विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए नरकोपी पहुंचकर संपन्न हुआ। यहां उलमा ने पैगंबर-ए-इस्लाम

की सीरत, उनकी शिक्षाओं, ईसानियत, प्रेम, दया, भाईचारे और आपसी सौहार्द के संदेश पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर उप प्रमुख सह मंत्री प्रतिनिधि मुदस्सिर हक ने कहा कि ईद मिलादुन्नी आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का संदेश देने वाला मुबारक अवसर है। पैगंबर हजरत मुहम्मद का जीवन पूरी ईसानियत के लिए प्रेरणास्रोत है।

उनकी शिक्षाएं हमें प्रेम, दया, विनम्रता और शांति का रास्ता दिखाती हैं। उन्होंने लोगों से पैगंबर-ए-इस्लाम की शिक्षाओं पर अमल करते हुए समाज में शांति, एकता और भाईचारा कायम रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने जुलूस में शामिल सभी अकीदतमंदों एवं बेड़ो प्रखंडवासियों को ईद मिलादुन्नी की दिली मुबारकबाद दी।

सिल्ली-मुरी में हर्षोल्लास से मनाया गया जश्ने ईद मिलादुन्नी, भव्य जुलूस में उमड़े अकीदतमंद

बिभा संवाददाता
सिल्ली/मुरी : सिल्ली एवं मुरी आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के द्वारा जश्ने ईद मिलादुन्नी का त्यौहार बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पर्व को लेकर भव्य जुलूस निकाला। यह जुलूस बड़ामुरी गांव होते हुए छोटा मुरी मस्जिद पहुंचा, जहां सलातो सलाम का नजराना पेश कर क्षेत्र में शांति, अमन,चैन और आपसी भाईचारे की दुआएं कर जुलूस का समापन किया गया।जुलूस में लोग पूरे उत्साह और अकीदत के साथ आगे बढ़ते रहे।लोगों ने एक दूसरे को गले लगा कर ईद मिलादुन्नी की बधाइयां दी।वहीं कमटी के मोहम्मद फारूक ने बताया कि आज ही के दिन मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जिसकी खुशी में मुस्लिम समुदाय के लोग जश्न ए ईद मिलादुन्नी के नाम पर मानते हैं।इन्होंने हमेशा अमन चैन की



सीख हम लोगों के बीच दी है इसलिए इस त्यौहार को शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सिल्ली में मदीना मस्जिद कमिटी सिल्ली से होते हुए ग्राम विकास स्कूल से सिल्ली थाना परिसर से वापसी होते हुए मदीना मस्जिद पहुंचे।इस मौके पर मस्जिदों को हरे रंग एवं तोरण से सजाया गया था। जुलूस में मोहम्मद यासिन,शह।दत,मोह म्मद

अनवर,मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद अब्बास,मुबारक, मजीद आलम, मोहम्मद अजीम,मोहम्मद हासिम,मोहम्मद मंजूर आलम, नूर मोहम्मद,मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद सुमेद,मोहम्मद दाऊद अली,मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद जसीम,शेख मुख्तार, अजीम अंसारी,फिरोज अंसारी,मकसूद आलम, मोहम्मद उस्मान समेत सैकड़ो लोग शामिल रहे।

कैब्रियन पब्लिक स्कूल में ह्यूमैनिटीज फेस्ट एपिस्टीम आयोजित

रांची। कैब्रियन पब्लिक स्कूल, ककि रोड में बुधवार को ह्यूमैनिटीज फेस्ट एपिस्टीम-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की निदेशक सह प्राचार्या परमजीत कौर, पार्श्व गायिका मोनिका मुंडू, कुंदन कुमार चौधरी और रेडियो-टेलीविजन कलाकार सुकुमार मुखर्जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर परमजीत कौर ने कहा कि मनुष्यता का धर्म सर्वोपरि है। ज्ञान की सभी शाखाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मानविकी के केंद्र में मनुष्यता है। उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटीज विद्यार्थियों को बेहतर और चरित्रवान नागरिक बनाने के साथ उनके समग्र विकास की नींव मजबूत करता है। यह वर्तमान समय और शिक्षा व्यवस्था की भी महत्वपूर्ण जरूरत है। टैगलाइन पर आधारित एपिस्टीम-2026 में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और समकालीन विषयों को प्रभावी ढंग से सामने रखा। एहसास कार्यक्रम में समकालीन समस्याओं की जीवंत प्रस्तुति दी गई, जबकि माइम के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। फ्लैग ऑफ नेशन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ वायुसेना, नौसेना, थलसेना, प्रशासन और झारखंड पुलिस के झंडों की जानकारी दी। झीम यूटोपिया में काल्पनिक देशों के संविधान, शासन व्यवस्था, मुद्रा, मानचित्र, खानपान और पोशाक की परिकल्पना प्रस्तुत की गई।

नन्हे हाथों ने लिखी चिट्ठी, गुमला डाकघर पहुंचकर पत्रपेटी में डाले पत्र

बिभा संवाददाता
गुमला। रक्षाबंधन के अवसर पर चिट्ठी और डाक सेवा की परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने की पहल बुधवार को गुमला मुख्य डाकघर में उस समय देखने को मिली जब बाल पाठशाला प्ले स्कूल, गुमला के नन्हे बच्चे पहली बार सामूहिक रूप से डाकघर पहुंचे। अपने परिजनों के लिए लिखे पत्र स्वयं पत्रपेटी में डाले। बच्चों ने लिखालय में अपने हाथों से राखिया तैयार कीं और उन्हें डाक विभाग के लिफाफों में रखकर परिजनों के नाम पत्र भी लिखे।



बच्चों को उत्साह के साथ पत्र पोस्ट करते देखकर गुमला मुख्य डाकघर के कर्मचारी भी काफी प्रसन्न हुए। बच्चों में राखी और पत्र अपने परिजनों तक पहुंचाने को लेकर खासा उत्साह रहा। विद्यालय की प्राचार्या और

शिक्षक भी बच्चों के साथ डाकघर पहुंचे और उनका उत्साह बढ़ाया। डाकघर परिवार ने बच्चों का स्वागत करते हुए उन्हें चॉकलेट खिलाई। इस अवसर पर पोस्टमास्टर शिव शंकर ठाकुर ने कहा कि रक्षाबंधन

पर डाक के माध्यम से राखी और शुभकामना संदेश भेजने को लेकर लोगों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि चिट्ठी केवल कामज का टुकड़ा नहीं, बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों को जोड़ने वाला माध्यम है। बच्चों को बचपन से पत्र लेखन और डाक सेवा से जोड़ना भावनात्मक विरासत को आगे बढ़ाने की सुंदर पहल है। उन्होंने लोगों से भाई-बहनों और प्रियजनों को राखी और शुभकामना संदेश डाक के माध्यम से भेजने की अपील की। इस अवसर पर गुमला मुख्य डाकघर के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव निरंजन ओहदार, सुनील सहित अन्य मौजूद थे।



सामाजिक संवेदनशीलता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह पहल केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि समाज के वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का संदेश भी देती है।विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई ये राखियां केवल कला का नमूना नहीं हैं, बल्कि इनमें करुणा और सामाजिक दायित्व की भावना भी निहित है। बच्चों के एक छोटे से रचनात्मक प्रयास को स्लम क्षेत्र की बेटियों के कल्याण से जोड़ना अत्यंत सराहनीय है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, संवेदनशीलता और समाज

सिल्ली बाजार में रक्षाबंधन की रौनक, 5 रुपये से 150 रुपये तक की आकर्षक राखियां बनीं पसंद



बिभा संवाददाता
सिल्ली: रक्षाबंधन पर्व को लेकर सिल्ली बाजार में रौनक बढ़ गई है। बाजार की दुकानें रंग-बिरंगी राखियों से सज गई हैं और भाई-बहन के इस पवित्र प्रेम के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। दुकानों में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हर तरह की आकर्षक राखियां उपलब्ध हैं। इस बार बाजार में रेशम धागे वाली पारंपरिक राखी के साथ-साथ भाभी राखी, मोतियों वाली डिजाइनर राखी, कार्टून कैरेक्टर और खिलौना थीम वाली राखियां लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं। छोटे बच्चों के लिए लाइट वाली राखी , छोटा भीम और डोरेमॉन वाली

राखियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दीपक स्टूडियो के दुकानदार दीपक लोहरा ने बताया कि इस बार ग्राहक बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में 5 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की अलग-अलग डिजाइन और कीमत वाली राखियां उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि लोग महंगी राखियों की बजाय सुंदर डिजाइन, मोतियों और हल्के वजन वाली राखियों को अधिक पसंद कर रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में राखियों के साथ-साथ मिठाइयों की की दुकान में भीड़ बढ़ी है। रसगुल्ला, चमचम और कई प्रकार के मिठाइयों की मांग तेज हो गई है।

मतदाता सूची में उम्र की विसंगतियों को दूर करें: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

बिभा संवाददाता

रांची : झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची में उम्र से संबंधित तार्किक विसंगतियों का पूरी गंभीरता और सावधानी से निष्पादन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि यदि कोई विदेशी नागरिक खतियान या वंशवली में छेड़छाड़ कर खुद को भारतीय नागरिक या किसी परिवार का वंशज बताकर मतदाता सूची में शामिल होने का प्रयास करता है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित



निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) को दी जाए और ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट

किया कि उम्र की जांच केवल एक प्रविष्टि या किसी एक दस्तावेज तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि एक ही माता-पिता की एक से अधिक संतानें पंजीकृत हैं, तो उनके जन्म दस्तावेजों

और आयु में तार्किक अंतर का एक साथ मिलान किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी उम्र में जानबूझकर छेड़छाड़ की जाती है। ऐसे मामलों में ईआरओ को सभी उपलब्ध दस्तावेजों का समग्र परीक्षण करना चाहिए। मतदाता को अपना पक्ष रखने और सही दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर देने के बाद ही नियमानुसार कारणयुक्त आदेश (स्पेकिंग ऑर्डर) पारित किया जाना चाहिए। फजीवों के लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा

कि यदि किसी विदेशी या अपात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने में किसी खतियान धारी, परिवार के सदस्य या स्थानीय व्यक्ति की मिलीभगत पाई जाती है, तो उसके खिलाफ भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा अन्य सुसंगत कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, किसी महिला मतदाता के पारिवारिक संबंध के सत्यापन के दौरान आवश्यकता पड़ने पर उसके पति/पतिव्रत और वंश की जानकारी भी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। तार्किक प्रक्रिया पूरी तरह तथ्यपरक रहे। के. रवि कुमार ने कहा कि विशेष गहन

पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य एक शुद्ध, त्रुटिरहित और स्थायी मतदाता सूची तैयार करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरी सुनवाई और नोटिस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी वैध भारतीय नागरिक को अनावश्यक रूप से परेशान करना नहीं है, बल्कि त्रुटियों को सुधारना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी पात्र भारतीय का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा और कोई भी अपात्र या विदेशी नागरिक इसमें शामिल नहीं हो सकेगा। इस राष्ट्रीय कार्य की सफलता के लिए उन्होंने सभी हितधारकों से पूर्ण सहयोग की अपील की है।

अधिकारों की आवाज उठाने वाला हर व्यक्ति भाजपा की नजर में संदेहास्पद : विनोद

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और भाजपा पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि भाजपा की नजर में आदिवासी-मूलवासी, गरीब और अपने अधिकारों की आवाज उठाने वाला हर व्यक्ति संदेह की नजर से देखा जा रहा है। सवाल है कि क्या भाजपा की नजर में हर झारखंडी और केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति दिमागी नकसल है।

विनोद पांडेय ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञापित में कहा कि आंकड़े गिनाने से पहले उन गांवों का दर्द समझना चाहिए, जिनकी जमीन खनन के लिए गई, जंगल उजड़ें और पीढ़ियां विस्थापन झेलती रहीं। उन्होंने रघुवर दास के एमएमडीआर संशोधन अधिनियम



संबंधी बयान पर कहा कि 11 हजार करोड़ रुपये और करोड़ों प्रतिशत की चर्चा से मूल सवाल नहीं छिपाया जा सकता। यदि खनिज से राज्य को लाभ मिल रहा है तो प्रभावित गांवों में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार की कमी क्यों है। पांडेय ने कहा कि झामुमो खनन या औद्योगिक विकास का विरोधी नहीं है। उसकी मांग जमीन का सम्मान, जंगल और आदिवासी अधिकारों की रक्षा, स्थानीय युवाओं को रोजगार तथा खनिज संपदा में झारखंडी हित की प्राथमिकता है।

बाइक चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की दस बाइक के साथ आठ आरोपित गिरफ्तार



बिभा संवाददाता

रांची। राजधानी रांची के धुर्वा थाना पुलिस ने वाहन चेंकिंग के दौरान बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की 10 बाइक बरामद की है। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गिरोह रांची और सीमावर्ती जिलों में सक्रिय था और साप्ताहिक बाजारों से मोटरसाइकिल चोरी कर उनके नंबर प्लेट बदलकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेचता था। एसपी ने बताया कि धुर्वा थाना पुलिस सिटियों-धुर्वा मार्ग स्थित स्वर्णखा नदी पुल के पास करीब 2:30 बजे वाहन चेंकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल पर सात तीन लोग पुलिस को देखकर बाइक घुमाकर सिटियों की ओर भागने का प्रयास करने लगे।

पुलिस ने पीछा कर तीनों को पकड़ा। पूछताछ में बाइक चोरी की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस कड़ाई से पूछताछ शुरू की और उसके निशानदेही पर छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी टीम ने चोरी के 10 बाइक बरामद किए और चोरी के वाहनों की खरीद-बिक्री में शामिल अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों में भरत बैठा (26), सुनील करमाली (25), रोहित उरांव (22), रोहित कुमार मुंडा (28), प्रदीप उरांव, संजय गंडू (22), सरजू मुंडा और सुमित उरांव (29) शामिल हैं। इनमें कई आरोपितों के खिलाफ पहले भी वाहन चोरी और अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। छापेमारी टीम में डीएसपी नीरज कुमार झा, धुर्वा थाना प्रभारी अनिल कुमार तिवारी सहित सशस्त्र बल शामिल थे।

बूटी मोड़ में महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति का भूमि पूजन संपन्न, कोलकाता के कारीगर बनाएंगे मठ्य पंडाल

रांची(बिभा) : राजधानी के बूटी मोड़ स्थित महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के प्रांगण में बुधवार को दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण को लेकर भूमि पूजन सह प्रथम खूटा-पूजा का कार्यक्रम पूरे विधि-विधान और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। माता के जयकारों के बीच हुए इस आयोजन में समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा गया। पूजा संपन्न होने के बाद पूरे बूटी मोड़ क्षेत्र में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गईं। समिति की ओर से जानकारी दी गई कि इस वर्ष माता का दरबार बेहद खास होगा। कलकत्ता से बुलाए गए कुशल कारीगरों द्वारा इस बार एक भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराया जाएगा, जो इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। पंडाल निर्माण को लेकर तैयारियां आज से ही जोरों पर शुरू कर दी गई हैं। इस शुभ अवसर पर समिति के मुख्य संरक्षक व पूर्व सांसद रामटहल चौधरी, अध्यक्ष रुद्र नारायण महतो, श्री महावीर मंडल राँची के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार पिंग्कू और स्थानीय पार्षद अवधेश बैठा मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

नाई समाज विकास समिति ने खिजरी विधायक राजेश कच्छप का जताया आभार

रांची(बिभा)। नाई समाज विकास समिति, रांची की केंद्रीय कमिटी के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को खिजरी विधायक सह कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। समिति के सदस्यों ने वर्ष 2020 में झारखण्ड विधानसभा में हजाम/नाई जाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के लिए विधायक राजेश कच्छप के प्रति आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि समाज की समस्याओं और मांगों को विधानसभा के सदन में उठाकर उन्होंने नाई समाज की आवाज को मजबूती प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रतिनिधि मंडल ने नापित जाति का प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई, नाई/हजाम जाति को सी.एन.टी. एक्ट की समस्या, झारखण्ड में केश कला बोर्ड/आयोग का गठन करने एवं जाति एवं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा किया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि नाई समाज के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग और समाज की एकजुटता अत्यंत आवश्यक है। समिति ने भविष्य में भी समाज से जुड़े मुद्दों को उचित मंच पर उठाने के लिए विधायक राजेश कच्छप से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। विधायक राजेश कच्छप ने नाई समाज के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए समाज के विकास एवं अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान नाई समाज विकास समिति के विरेन्द्र प्रसाद, शिवशंकर हजाम, सुनील प्रमाणिक, राजेन्द्र प्रमाणिक, दिनेश चन्द्र प्रमाणिक एवं सदस्य उपस्थित रहे।

बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखें बाबूलाल : राकेश

रांची(बिभा)। प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर हमला करते हुए कहा कि अगर छात्रों के घुंटे पर पत्र लिखना ही उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो वे अपनी नैतिकता का परिचय बिहार में भी दें। बिहार में अपने अधिकार और मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल पर बाबूलाल मरांडी को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखना चाहिए। राकेश सिन्हा ने बुधवार को प्रेस विज्ञापित जारी कर कहा कि भाजपा नेताओं की राजनीति में सुविधा के हिसाब से नैतिकता बदल जाती है। झारखंड में छात्रों के प्रति चिंता और बिहार में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर चुप्पी-यह दोहरा चरित्र आखिर क्यों। उन्होंने कहा कि यदि बाबूलाल मरांडी वास्तव में छात्रों के हितैषी हैं तो उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार सरकार से भी जवाब मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है। सरकार का दायित्व है कि वह छात्रों की बात सुने, संवाद करे और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले। लाठी और वाटर कैनन किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की पहली प्रतिक्रिया नहीं हो सकती।

क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी मंत्री शिल्पी

रांची(बिभा)। मंत्री शिल्पी नेहा तिकरी 27 अगस्त 2026 को बेंगलुरु स्थित क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। विश्वविद्यालय के एल्यूमिनी रिलेशन्स सेल की ओर से आयोजित कार्यक्रम का विषय फ्रॉम एजुकेशन टू एंपावर : यूथ लीडरशिप, इंटरप्रैन्डो रशीप एंड इक्लूआसिव ग्रोथ रखा गया है। यह जानकारी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की ओर से बुधवार को जारी पोस्टर के माध्यम से दी गई। बताया गया कि कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, कृषि, नवाचार, युवा नेतृत्व और समावेशी विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पैनेल चर्चा होगी।

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हाल में लाया गया खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमडीआर) राज्य और राष्ट्रहित में है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस संशोधन की गलत व्याख्या कर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। रघुवर दास बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एमएमडीआर संशोधन झारखंड के हितों के खिलाफ नहीं, बल्कि राज्य को उसकी खनिज संपदा का अधिकतम लाभ दिलाने और वैध धर्म को पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर झारखंड के खनिज संसाधनों की



झामुमो-कांग्रेस के संरक्षण में धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, साहेबगंज, दुमका और शिकारीपाड़ा समेत कई क्षेत्रों में कोयला, बालू और पत्थर के अवैध कारोबार से जुड़े सिंडिकेट सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दलों के जेल जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे दलों से एमएमडीआर संशोधन पर किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दास ने कहा कि मौजूदा विवाद केवल 11 हजार करोड़ रुपये के उपकर (सेस) तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या वित्तीय अनिश्चितता का

लूट को संरक्षण देने का आरोप लगाया। रघुवर दास ने पत्थर के अवैध खनन से जुड़े मामलों में झामुमो के नेताओं और सरकार के एक मंत्री को जेल जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे दलों से एमएमडीआर संशोधन पर किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दास ने कहा कि मौजूदा विवाद केवल 11 हजार करोड़ रुपये के उपकर (सेस) तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या वित्तीय अनिश्चितता का

उर्सलाइन कॉन्वेंट में पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ नेत्रदान जागरूकता सेमिनार

बिभा संवाददाता

रांची। राष्ट्रीय 41 वें नेत्रदान पखवाड़ा के तहत बुधवार को उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल, रांची में पेंटिंग प्रतियोगिता और नेत्रदान जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। 25 अगस्त से आठ सितंबर 2026 तक चलने वाले नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, कश्यप मेमोरियल आई बैंक और आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। प्रतियोगिता में स्कूल की छात्राओं ने भाग लेकर अपनी कलाकृतियों के माध्यम से नेत्रदान का संदेश दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एमएचएम के मिशन डायरेक्टर शशि प्रकाश झा ने कहा कि मृत्यु के बाद नेत्रदान के लिए परिजनों को प्रेरित करने और उन्हें भावनात्मक सहयोग देने के लिए अस्पतालों में प्रशिक्षित ग्रीफ काउंसलर्स एवं आई डोनेशन



कोऑर्डिनेटर्स की तैनाती को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मृत्यु के चार से छह घंटे के भीतर कॉर्निया प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन और त्वरित प्रतिक्रिया टीम नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. भारती कश्यप ने कहा कि जानकारी के अभाव में लोग नेत्रदान को लेकर कई भ्रांतियों से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि उम्र, लिंग और ब्लड ग्रुप की बाधता नहीं है। मोतियाबिंद सहित कई आँखों की सर्जरी के बाद भी नेत्रदान संभव है। प्रक्रिया के बाद घेरे की विकृति नहीं होती और इसे सामान्यतः 15-20 मिनट में पूरा

किया जा सकता है। घर पर मृत्यु होने की स्थिति में भी निर्धारित समय में आई बैंक की टीम प्रक्रिया कर सकती है। अंगों की खरीद-बिक्री गैरकानूनी है। डॉ. निधि गडकर कश्यप ने बताया कि 2019 से कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में 500 से अधिक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का नेत्रदान दो कॉर्नियल ट्रिप्टीन लोगों के जीवन में रोशनी ला सकता है। सेमिनार में डॉ. राहुल किशोर सिंह, अनिमा किस्कू और प्राचार्या सिस्टर मेरी ग्रेस सहित अन्य लोग मौजूद थे।

जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन: अमीषा प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आंदोलनकारी अमीषा प्रसाद ने पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बुधवार को ग्रैंड प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कई आरोप लगाए। अमीषा ने आरोप लगाया कि झूठे मुकदमों के जरिए छात्रों और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अमीषा प्रसाद ने आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने वाले शहबाज आलम पर भी निशाना साधा। उन्होंने उन्हें आमने-सामने बातचीत यानी टेबल टॉक की खुली चुनौती दी। अमीषा ने कहा कि यदि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं तो संबंधित पक्ष सामने आकर उन आरोपों



के प्रमाण पेश करें। आमने-सामने बातचीत से यह स्पष्ट हो सकता है कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। दहलसल, शहबाज आलम की ओर से अमीषा प्रसाद के खिलाफ दंगा फैलाने और मारपीट जैसे आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि, अमीषा का दावा है कि आंदोलन के दौरान छात्रों ने किसी भी तरह के ग्रेवेटेक्ल का उल्लंघन नहीं किया। अमीषा प्रसाद ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस या वार्ंट के घर से हिरासत में लिया गया

और करीब छह से सात घंटे तक रखा गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सदर थाना प्रभारी की ओर से उन्हें पुराने मामलों में फंसाते का प्रयास किया गया। अमीषा के मुताबिक, मीडिया के सामने भी उनके संबंध में गलत जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने आरोप लगाया कि करीब 14 पुरुष छात्रों, जिनमें रविंद्र और कुणाल सर समेत अन्य लोग शामिल हैं, के खिलाफ छेड़खानी जैसे गंभीर आरोपों में कथित रूप से झूठी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। मंच से जुड़ी छात्राओं ने इन आरोपों को गलत बताया है, कहा कि कानून का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कर निर्दोष छात्रों को फंसाते की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर सदस्य प्रतीमा कुमारी ने प्रशासन पर दोहरे रवैये का

आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एक पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान छात्रों के समर्थन में पहुंची महिलाओं के साथ मारपीट और बदनसज्जी की गई। प्रतीमा के अनुसार, इस मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए वह लगातार दो दिनों तक थाने ने चक्कर लगाती रहीं, लेकिन पुलिस ने उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। मंच ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के अलग-अलग जिलों में पुलिस की मौजूदगी में छात्रों पर बल प्रयोग किया गया। प्रेस वार्ता में मंच ने जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच सीआईडी के बजाय सीबीआई से कराने की मांग दोहराई। इसके साथ ही आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज कथित फर्जी मुकदमे वास लेने और जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रूपांतरित करने के माध्यम से कराने की मांग भी रखी गई।

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना सं.: ईएल-41-सोलर-पीपीपी-26, दिनांक 24.08.2026, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य), पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, पिन-713301 द्वारा ख्यातिप्राप्त निविदाकारों जिनके पास वैध विद्युत ठेकेदार का लाइसेंस है एवं निम्नलिखित कार्य को पूरा करने में वित्तीय रूप से सक्षम हैं, से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: कार्य का नाम एवं इसका स्थान: आसनसोल-मंडल: पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीपी) के साथ आईएससीओ मॉडल के माध्यम से आसनसोल मंडल के विभिन्न स्थानों पर बिजली का उत्पादन और आपूर्ति करने के उद्देश्य से कुल 1500 के डबल्यूपी क्षमता प्रणाली (पीपीपी मोड) के ग्रीड कनेक्टेड स्लफ-टॉप सोलर फोटो वोल्टेइक मॉडल के स्थापना। निविदा मूल्य : ₹. 22,23,86,424.4, निविदा कागजात का मूल्य : 34,810/-, बजाना राशि : ₹. 16,02,000/-, कार्य के लिए समान अवधि : 240 दिन। बंद होने एवं खुलने की तिथि और समय : दिनांक 23.09.2026 को 15.00 बजे। संपूर्ण विवरण रेलवे की वेबसाइट है: www.ireps.gov.in में देखा जा सकता है। ASN-230/2026-27 निविदा सूचना वेबसाइट www.e.indianrailways.gov.in/ww.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है। हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 200 किलो लड्डू जब्त

बिभा संवाददाता

लोहरदगा। आगामी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की मांग में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग, लोहरदगा द्वारा शहरी क्षेत्र में नियमित निरीक्षण एवं निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। पर्व के दौरान मिठाइयों की बिक्री में वृद्धि को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सुरक्षित भंडारण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बुधवार को इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। मेसर्स भोला साव के प्रतिष्ठान में बिना वैध लाइसेंस के



बड़ी मात्रा में लड्डू का निर्माण करते पाया गया। करीब 150 किलोग्राम लड्डू में फंगस लगी हुई थी, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। संबंधित संचालक को खाद्य कारोबार के लिए वैध लाइसेंस लेने

का निर्देश दिया गया। न्यू रोड स्थित मेसर्स अनुराग गुप्ता के प्रतिष्ठान में अस्वच्छ वातावरण में लड्डू का निर्माण करते पाया गया। संचालक पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पांच हजार

रुपये का अर्थदंड लगाया गया तथा सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। वहीं, बड़ा तालाब स्थित मेसर्स जिम्मी स्टोर तथा मेसर्स एम स्टार बेकरी के प्रतिष्ठानों में बिक रहे लड्डूओं की जांच के दौरान हानिकारक अखाद्य रंग की मिलावट की पुष्टि हुई। दोनों प्रतिष्ठानों से लगभग 50 किलोग्राम मिलावटी लड्डू जब्त किए गए, ताकि इस प्रकार के खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच सकें। संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस भी जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को पर्व के दौरान

विशेष सावधानी बरतने, गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल का उपयोग करने तथा मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों को निर्धारित स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण मानकों के अनुरूप रखने का निर्देश दिया है। विभाग ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। उपायुक्त लोहरदगा के निर्देशानुसार आगामी त्योहार को देखते हुए इस प्रकार के औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोइन अख्तर, विश्वनाथ गराई तथा विभाग के सहायक कर्मी रजनीश कुमार मौके पर मौजूद थे।

भारत विकास परिषद केवल एक संगठन नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार और सामाजिक समरसता के माध्यम है : गोयल

बिभा संवाददाता

रामगढ़: भारत विकास परिषद, रामगढ़ का छठा पद स्थापना एवं शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही उत्साह, गरिमा एवं भव्यता के साथ रोटरी हॉल, थाना चौक रामगढ़ में मंगलवार की संध्या आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निवृत्ति गुप्ता द्वारा गणेश वंदना से हुआ। मंच संचालन उमेश राजगढ़िया ने प्रभावशाली ढंग से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि दक्षिण झारखंड प्रांत के महासचिव अरुण कुमार मिश्रा एवं प्रांतीय संपर्क सचिव नवीन पाठक उपस्थित रहे। संस्थापक अध्यक्ष गोविंद मेवाड़ ने अतिथियों एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। समारोह में निवर्तमान सचिव मनमोहन सिंह लांबा ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों एवं सेवा कार्यों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात प्रांतीय



महासचिव अरुण कुमार मिश्रा ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में अध्यक्ष: अनिल कुमार गोयल, उपाध्यक्ष सचिन अग्रवाल, मनमोहन सिंह लांबा, आलोक रतन चौधरी, सचिव प्रदीप कुमार शर्मा, सह सचिव आलोक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष: निलेश गुप्ता, सह कोषाध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल, सलाहकार समिति में गोविंद मेवाड़, उमेश राजगढ़िया, अनमोल सिंह, मीडिया प्रभारी अमित साहू, संपर्क प्रमुख रामप्रवेश गुप्ता, संस्कार प्रमुख वरुण बगड़िया, सेवा प्रमुख अजय अग्रवाल, परिवारण प्रमुख सूरज अग्रवाल, महिला एवं बाल

विकास प्रमुख पूनम सिंह, कार्यकारिणी सदस्य में भरत गोयल, विकास अग्रवाल, रोहित पंसारी, आयुष अग्रवाल है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल कुमार गोयल ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सेवा एवं सामाजिक सरोकारों को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण संकल्प लिए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कम से कम 51 निर्धन कन्याओं के विवाह में सहयोग एवं आयोजन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रभावी कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उन्होंने रामगढ़ शहर में कम से कम 101 कल्पवृक्षों का रोपण करने तथा उनके संरक्षण एवं पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करने की

ईद मिलादुन्नबी पर चीरी में उमड़ा आस्था का सैलाब, मोहम्मद साहब की याद में निकला भव्य जुलूस



बिभा संवाददाता

कुड्डू। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस के अवसर पर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कुडू प्रखंड के चीरी में बुधवार 26 अगस्त को भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में धार्मिक नारों की गूंज सुनाई दी। हाथों में इस्लामी झंडे लिए लोगों ने शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से जुलूस में भाग लिया। जुलूस के माध्यम से शांति, आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी तरह मुस्तैद रहा। चीरी से निकला मुख्य जुलूस चीरी नवाटोली, चीरी बरवाटोली और चीरी आजाद

बस्ती होते हुए विभिन्न क्षेत्रों से गुजरा। वहीं सुकुमरा से आया जुलूस भी चीरी पहुंचा और तीनों बस्तियों का भ्रमण किया। जगह-जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। इस दौरान हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज मौजिबुल्लाह और हाफिज दानिस राजा खान ने हजरत मोहम्मद के जीवन और उनके संदेश पर प्रकाश डाला। नात प्रस्तुत कर लोगों को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया गया। जुलूस की अगुवाई हाफिज रहमान, हाफिज मौजिबुल्लाह, हाफिज दानिस राजा खान, मौलाना फुरकान, हाफिज जफर अब्बास, मौलाना गुलाम रसूल, हाफिज एनामुल और मौलाना गुलजार ने की।

कल मनेगा रक्षाबंधन, सुबह से दिनभर बांधा जा सकेगा रक्षा सूत्र

कल 28 अगस्त को सुबह 10:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि, इस बार भद्रा का नहीं रहेगा विशेष प्रभाव

प्रमोद खण्डलवाल

हजारीबाग। भाई-बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व इस वर्ष 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगी है। राखी, मिठाई और उपहारों की खरीदारी के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं। वहीं घरों में भी रक्षाबंधन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना करंगी। रक्षाबंधन के शुभ समय को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। इस संबंध में हजारीबाग के प्रसिद्ध आचार्य दीपक पांडेय ने



सुबह 10:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि

आचार्य दीपक पांडेय ने बताया कि पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त, शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे तक रहेगी। रक्षाबंधन पर्व में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इसी कारण इस बार पर्व को लेकर लोगों में विशेष उत्साह है। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधने के लिए दिनभर का समय अनुकूल रहेगा।

भद्रा का भी नहीं रहेगा विशेष प्रभाव

रक्षाबंधन के अवसर पर भद्रा का विशेष रूप से विचार किया जाता है। मान्यता के अनुसार भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधने से बचने की परंपरा रही है। हालांकि, इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा का ऐसा विशेष प्रभाव नहीं है, जिसके कारण रक्षा सूत्र बांधने में किसी प्रकार की बाधा हो। इसलिए बहनें श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं।

बताया कि इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधने को लेकर विशेष परेशानी नहीं है। प्रातःकाल से लेकर दिनभर बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। अपनी सुविधा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार दिन में किसी भी समय रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है।

डोरंडा गर्ल्स मिडिल स्कूल की पूर्व छात्राओं ने की संघ के गठन की पहल

रांची। डोरंडा गर्ल्स मिडिल स्कूल, डोरंडा की पूर्व छात्राओं ने विद्यालय की सभी पूर्व छात्राओं को एकजुट कर बुधवार को पूर्व छात्रा संघ के गठन की पहल की है। इस संबंध में पूर्व छात्राओं की ओर से डोरंडा गर्ल्स मिडिल स्कूल एवं सोसाइटी, डोरंडा के सचिव को औपचारिक अनुरोध पत्र सौंपकर संघ के गठन की अनुमति एवं आवश्यक मार्गदर्शन देने का आग्रह किया गया है। इस पहल का नेतृत्व पूर्व छात्राएं डॉ मऊ संतारा और रजनी बख्शी कर रही हैं। पूर्व छात्राओं ने कहा कि एक संगठित मंच के माध्यम से विद्यालय की शैक्षणिक, सामाजिक और अन्य आवश्यक गतिविधियों में सहयोग किया जा सकेगा। साथ ही, इसके विद्यालय की प्रतिष्ठा, गौरवशाली विरासत और गरिमा को संरक्षित एवं और मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

लातेहार: कोयला परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला बोल, जनसुनवाई रद्द करने की मांग

बिभा संवाददाता

लातेहार/बालूमाथ: लातेहार के बालूमाथ में एन.एल.सी. कंपनी द्वारा प्रस्तावित 'नार्थ धाघू (वेस्टर्न पार्ट)' कोयला परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। खरटिया और भैंसादोन गांव के लोग एकजुट होकर आगामी 27 अगस्त को प्रस्तावित जनसुनवाई का कड़ा विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि कंपनी उनकी उपजाऊ जमीन को साजिशान बंजर बताकर हथियाना चाहती है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर कंपनी की नजर है, वह पीढ़ियों से उनके परिवारों के भरण-पोषण का मुख्य आधार रही है। खेतों के माध्यम से यहाँ का एक किसान परिवार सालाना लगभग तीन से चार लाख रुपये तक की आय अर्जित कर लेता है। यह जमीन उनके पुरखों ने आने वाली पीढ़ियों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए सुरक्षित रखी थी। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि उनका जीवन है। इसके छिन जाने से उनके सामने रोजी-रोटी और अस्तित्व का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा, जिसे वे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इस मामले में जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी ने कंपनी और प्रशासन के रवैये पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कंपनी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना शुरू करने से पहले कंपनी का कोई भी



प्रतिनिधि प्रभावित गांवों में ग्रामीणों से संवाद करने नहीं पहुंचा। ग्रामीणों को विश्वास में लिए बिना उनके जीवन से जुड़े फैसले थोपना अत्यंततांत्रिक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रभावित गांवों के बजाय प्रखंड स्तर पर जनसुनवाई आयोजित करना, असल में ग्रामीणों की आवाज को कमजोर करने का एक सोची-समझी साजिश है। बैठक के अंत में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने 27 अगस्त को होने वाली प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कंपनी को सीधे ग्राम सभा में आकर रोजगार, मुआवजा तथा पुनर्वास जैसे अहम मुद्दों पर पारदर्शी तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने सरकार और कंपनी को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज कर जबरन प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, तो ग्रामीण उग्र और चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बड़की चौपी में शोक सभा आयोजित, दी गई श्रद्धांजलि

लोहरदगा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बड़की चौपी के प्रांगण में 26 अगस्त 2026 को शोक सभा का आयोजन किया गया। विद्यालय के अभिभावक प्रतिनिधि सोमनाथ मुंडा के पिता एवं पूर्व मुखिया मुनिया देवी के ससुर सोमरा मुंडा के आकस्मिक निधन पर विद्यालय परिवार ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में आचार्य नरेश साहू ने दिवंगत आत्मा के बारे में भैया-बहनों को जानकारी देते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित भैया-बहनों, आचार्य एवं दीदी जी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिन्ट का मौन रखा तथा ईश्वर से प्रार्थना की। आचार्य गौरी शंकर नाथ शाहदेव ने अपने संबोधन में कहा कि सोमरा मुंडा का निधन विद्यालय परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं प्रधानाचार्य मनोहर मोदी ने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। शोक सभा में ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई। शोक सभा के पश्चात विद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया गया।



नबी हजरत मोहम्मद की अजमत और सीरत के संदेश के साथ हजारीबाग में निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी



बिभा संवाददाता

हजारीबाग : 1501वें जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के मुबारक अवसर पर बुधवार को हजारीबाग शहर में अकीदत, एहतराम और धार्मिक उत्साह के साथ जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला गया। जामा मस्जिद सेंट्रल कमेटी के तत्वावधान में आयोजित इस जुलूस में शहर के विभिन्न मोहल्लों के साथ-साथ आसपास के गांवों से करीब 100 जुलूस शामिल हुए। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। जामा मस्जिद रोड से निकाले गए जुलूस-ए-मोहम्मदी की निगरानी एदारा-ए-शरिया के चीफ काली एवं जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मुप्ती अब्दुल जलील सादी की देखरेख में की गई। जुलूस के दौरान नबी-ए-करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, सीरत और सुन्नतों का

बयान करते हुए नात-ए-रसूल पेश की गई। जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान दोपहर करीब 3 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। बारिश ने एक मिन्ट के लिए भी पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन बारिश की परवाह किए बिना अकीदतमंद पूरे उत्साह और अकीदत के साथ जुलूस में शामिल रहे। तेज बारिश के बावजूद लोगों का जोश और धार्मिक उत्साह चरम पर देखने को मिला। बारिश के बीच भी नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान में नारे गूंजते रहे। सरकार की आमद

मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबाह के उद्घोष से पूरा हजारीबाग शहर गुंजायमान होता रहा। अकीदतमंदों का यह जज्बा जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के प्रति उनकी गहरी आस्था और मोहब्बत को प्रदर्शित कर रहा था। जामा मस्जिद सेंट्रल कमेटी की ओर से जुलूस को सादगी और एहतराम के साथ निकालने की अपील पहले से की जा रही थी। कमेटी के पदाधिकारियों ने 12 रबीउल अव्वल से करीब दस दिन पूर्व ही विभिन्न गांवों और मोहल्लों में पहुंचकर कमेटीयों एवं मोहल्ले

के सदर-सचिवों से मुलाकात की थी। इस दौरान जुलूस को अनुशासित, सादगीपूर्ण और धार्मिक भावना के अनुरूप निकालने का आह्वान किया गया था। जुलूस के दौरान प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर के विभिन्न स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे जुलूस पर नजर रखते हुए शांतिपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए पूरी मुस्तैदी दिखाई। जुलूस के मार्ग में विभिन्न सामाजिक एवं सेवा संगठनों तथा जनप्रतिनिधियों की ओर से स्वागत शिंवर लगाए गए। इन शिंवरों में जुलूस में शामिल अकीदतमंदों के बीच फल, शरबत, पानी, बिस्किट सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया। सेवा और स्वागत के इस कार्य की लोगों ने सराहना की।

कुडू में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया ईद मिलादुन्नबी, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम

बिभा संवाददाता

लोहरदगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार को कुडू प्रखंड क्षेत्र में ईद मिलादुन्नबी का पर्व श्रद्धा, भाईचारे और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पूरा क्षेत्र धार्मिक नारों से गुंजता रहा। आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी संतोष उरांव और थाना प्रभारी अजीत कुमार पूरे जुलूस के दौरान मुस्तैद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। जुलूस को सफल बनाने में कुडू प्रखंड की विभिन्न समितियों और जुलूस आयोजन समितियों के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चीरी, माहौल है।



टाकू, लापूर, सुरुकू, नंतिलो, मिशन, पंडरा, बारीडीह, जोंजरो, कमले, नगड़ाटांड, जीमा, हुहहत और चेतुर समेत पूरे प्रखंड क्षेत्र के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मस्जिद के इमाम ने शांति, सुख-समृद्धि और भाईचारे के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के संदेशों को आगे बढ़ाने तथा समाज में आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की। आयोजन में शामिल लोगों ने भी शांति और भाईचारे का संदेश दिया। प्रशासन की सतकता और आयोजन समितियों के आपसी सहयोग से पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।

शिक्षित राष्ट्र के बिना विश्व गुरु की अवधारणा बेमानी



निर्मल रानी

देश में बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं की कमी व दुर्दशा तथा परीक्षा व्यवस्था में होने वाली घांघलियों व पेपर लीक जैसे मुद्दों ने देश के युवाओं को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। इससे घबराई सरकार कहीं स्कूल की वीडिओ ग्राफी करने पर रोक लगा रही है तो कहीं शिक्षण संस्थाओं की हकीकत को उजागर करने वालों पर सत्ता समर्थित गुंडों द्वारा हमला किया जा रहा है। और कहीं सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूल की अव्यवस्थाएँ दिखाने पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। परन्तु इस बीच कुछ जगहों से सकारात्मक ख़बरें भी आनी शुरू हुई हैं।



दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला मेतलॉजीयन स्मिथ ने 25 फरवरी 2020 को नई दिल्ली के मोतीबाग स्थित सर्वोदय सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए कई अन्य विदेशी मेमेन और प्रतिनिधिमंडल भी आ चुके हैं। समय-समय पर विभिन्न देशों के शिक्षाविद, राजनयिक और प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बुनियादी संरचना, कक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों का निरीक्षण करने दिल्ली आते रहे हैं। क्या इसी तरह के आधुनिक सरकारी स्कूल पूरे देश में संचालित नहीं हो सकते? क्या वजह है कि देश के अशिक्षित राज्यों में अनेकानेक सरकारी स्कूल भवन जर्जर हैं? कहीं स्कूल में भैंसों के तलेवे हैं तो कहीं ढुंग के नीचे व खुले असमान तले क्लास लगाई जा रही है। कहीं क्लासरूम नहीं। कहीं अध्यापक नहीं तो कहीं बिजली व पैसे का पानी नहीं तो कहीं शौचालय नहीं। कहीं बच्चे रोज नदी पार कर स्कूल आते

जोते हैं तो कहीं कीचड़ और दलदल भरी गड्ढेदार सड़कों से गुजर कर स्कूल आना जाता होता है। यदि देश की सरकारों शिक्षा के प्रति गंभीर होतों और उनका भारत को विश्वगुरु बनाने का हिंदीरा महज डोल पीटना न होता तो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रसन्ना बी. वरगले को महाशय में शिक्षा पर घटते बजट और सरकारी हरीयाध्यम के स्कूलों के बंद होने पर गहरी चिंता जताते हुये यथ न कहना पड़ता कि नासिक कुंभ मेले के लिए लगभग रु.32,000 करोड़ का भारी-भरकम बजट तय किया गया है। अगर इस राशि का मात्र 0.1% यानी लगभग रु.32 करोड़ भी शिक्षा पर खर्च किया जाता, तो राज्य के 100 से 125 बंद हो रहे मराठी स्कूलों को बचाया जा सकता था। अखिर जस्टिस प्रसन्ना को क्यों कहना पड़ा कि देश में बजट बढ़ने के बजाय घट रही है, जो पिछले कई वर्षों से 13% के आंकड़े पर भी नहीं छू सका है। उन्होंने गढ़चिरोली की एक घटना का उदाहरण भी दिया जहाँ

जरूरी सुविधाओं की कमी के कारण फर्श पर सोने की वजह से तीन छात्राओं की सांप के काटने से मौत हो गई थी। जस्टिस प्रसन्ना ने यह भी बताया कि उन्होंने स्वयं 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जिला परिषद के मराठी मीडियम स्कूल से की थी, जिसने उनके करियर में कभी बाधा नहीं डाली बल्कि उनके एंट्रेंस को और व्यापक बनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है।

देश में बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं की कमी व दुर्दशा तथा प्रीक्षा व्यवस्था में होने वाली धांधलियाँ व पेपर लीक जैसे मुद्दे ने देश के युवाओं को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। इससे खूबसूरत सरकार कहीं स्कूल की वीडियो ग्राफी करने पर रोक लगा रही है। तो कहीं शिक्षण संस्थाओं की हकीकत को उजागर करने वालों पर सत्ता समर्थित गुंडों द्वारा हमला किया जा रहा है। और कहीं सांशल मंडियां पर सरकारी स्कूल की अव्यवस्थाएं दिखावे पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। परन्तु इस बीच कुछ जगहों से सकारात्मक खबरें भी आनी शुरू हुई हैं। जैसेकि राजस्थान के रामपुर के उस स्कूल का नवनिर्माण करने का फैसला किया गया है जहाँ कॉलोच जवना पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सत्ता के समर्थक गुंडों ने मारपीट की थी। यह स्कूल भैंसों के तबले में चल रहा था। स्कूल की इमारत जगह होने के कारण एक स्थानीय ग्रामीण ने अपना नमज़ा जहाँ दौड़ रहे, इसी जगह भैंसों का चारा भी रखा जाता है और बच्चे भी पढ़ते हैं। पंजाब से भी खबर है कि सरकार ने स्कूलों के अपने नए भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन प्रीलीमिनेट जवनों का निर्माण मौजूदा मंजूरी से परे है अन्य खाली फ़िल्ड भवनों पर नए सिरि से किया जाएगा। हरियाणा में भी शिक्षा मंत्री द्वारा सरकारी स्कूलस का औचक निरीक्षण कर विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लेने व युवाधियों से संपर्क करने की खबर है। Gen Z और युवा पीढ़ी के आंदोलन से ही सही परन्तु शायद अब सत्ताघोषों की यह बात समझ आने लगी है कि शिक्षित राष्ट्र के बिना विश्व गुरु की अवधारणा पूरी तरह बेमानी है।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

जहर बांटते उद्योग

कुछ उद्यमी मुनाफ़ की अंधी हवस में इतने स्वास्थी हो जाते हैं कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को साफ़ किए बिना ही जलाधाराओं में बहा देते हैं। जबकि उनकी नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण व नदी-नालों को प्रदूषित न करें। हिमाचल प्रदेश स्थित बड़ी-नालागढ़ इलाके में कई औद्योगिक इकाइयाँ नदियों में जहरीले रसायन लगातार बहाती रही हैं। यह प्रदूषणकारक कचरा सिरसा नदी में बहा दिया जाता है, जो कालांतर सतलुज नदी में चला जाता है। यही वजह है कि आज सतलुज का प्रदूषित पानी जो चेतावनी दे रहा है उसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों भी नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। इसी आने वाले संकट के मद्देनजर ही बड़ी-नालागढ़ इलाके की अज्ञात औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है। जो मामले की गंभीरता को ही दर्शाता है। निरसिंह, यह संकट कोई नई समस्या नहीं है। जो हमारे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियम व कानूनों को लागू करने में तंत्र की बार-बार होने वाली विफलता को ही दर्शाता है। बड़ी-बोटड़ीवाला-नालागढ़ क्षेत्र से होने वाली औद्योगिक प्रदूषण के प्रामाणिक रिपोर्ट कई सालों से मौजूद हैं। दरअसल, यह जहरीला कचरा इस औद्योगिक क्षेत्र से गुजरने वाली सिरसा नदी में डाल दिया जाता है। सिरसा नदी इन प्रदूषक तत्वों को आगे की ओर बहा ले जाती है। कालांतर यह सतलुज नदी में जाकर मिल जाता है। इस बात के जवाब बार जांच भी की। शेनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में बिना डीट किए गए रसायनयुक्त कचरे व ठीक से ट्रीट न किए गए कचरे के बारे में उल्लेख किया गया है। ट्रिब्यूनल ने निर्णय का पालन न करने वाली इकाइयों तथा ट्रीटमेंट सिस्टम की खामियों की ओर इशारा किया है। दरअसल, फार्मास्यूटिकल प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि पारंपरिक ढंग से ट्रीटमेंट करने वाले सिस्टम से सक्रिय फार्मास्यूटिकल तत्व और एंटीबायोटिक के अवशेष पूरी तरह से नहीं हट पाते हैं। दरअसल, हाल के प्रकरण से एक और परेशान करने वाली विरोधीभासी बात सामने आई है। इस बाबत सूचना मिली थी कि रोपड़ हेडवर्क्स पर भारी मात्रा में जमा कचरे को नदी के बाहव की दिशा में बेफ़िक्रि से छोड़ दिया गया। निरसिंह, यह वह कचरा नुकसानकारक था, तो इसे नदी में छोड़ने से समस्या महज एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित ही हुई है। कायदे से हेडवर्क्स में जमा कचरे की वैज्ञानिक तौर-तरीकों से निगरानी की जानी चाहिए थी। सही मायने में प्रदूषणकारक कचरे को ठिकाने लगाने से पहले उसके सैंपल लेकर उसकी जांच-पड़ताल की जानी जरूरी थी। निश्चित रूप से यह संकट बड़ा है और तत्काल इसका समाधान किया जाना चाहिए था। वास्तव में इस मामले को हिमाचल बनाम पंजाब के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल नहीं बनने दिया जाना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि दोनों सरकारों मिलकर प्रदूषण फैलाने वाले कचरे का वास्तविक स्रोत तलाशें क्योंकि अभी तक कचरे के असली स्रोत का पता नहीं चल सका है।

चिंतन-मनन

कर्म के पाप-पुण्य में फंसे जाता है जीव

इश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान् समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूँकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीवविशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में इश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिये जीव को निर्दिष्ट करता रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उस क्या करता है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप-पुण्य में फँस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। चूँकि इस प्रकार वह आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत (पूर्वकृत) कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और वह समझ कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। इसीलिए हमने यह कहा है कि पाँच तत्त्वों- इश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार शास्त्र हैं, कर्म शास्त्र नहीं। परम चेतन इश्वर जीव से इस मामले में सहा हैं- भगवान् थाना जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रांतमूलक है। किंतु भगवान् जीवना भीतिकार से प्रभावित नहीं होती है। भगवान् प्रकृति हैं- जब वे इस भीतिकार वि में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर कौनका प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि वे भाववद्गीता में बोलते हैं। भीतिकार कर्म्य-ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य-जगत के विषयों में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान् भीतिकार हटि से कल्पित (दूषित) नहीं हैं। भगवद्गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कल्पित चेतना को शुद्ध करना है।



मनोज कुमार अग्रवाल

भा रत में नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी देश की आंतरिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए एक अत्यंत गंभीर संकट बन चुकी है। भौगोलिक रूप से भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों - पश्चिम गोल्डन क्रैसेंट (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान) और पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) के बीच स्थित है। इस संवेदनशील स्थिति के कारण देश में सीमा पार से बड़े पैमाने पर अवैध नशीले पदार्थों की आमद हो रही है।

नशीले पदार्थों की तस्करी में भारत की भौगोलिक स्थिति भी खासा जिम्मेदार है पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार से सटी खुली और जटिल जमीनी सीमाएं निगरानी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तस्करों द्वारा गुजरत और दक्षिणी राज्यों के विशाल तटीय क्षेत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अजब नशीले के सौंदभार तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं डाकनेट क्रिटो करेंसी और सीमा पार से ड्रग्स गिराने के लिए ड्रोन का बढ़ता प्रयोग खराब बढ़ा रहे हैं वहीं पारंपरिक अफीम-बग के स्थान पर हेरोइन, कोकीन और मेथामफेटामाइन जैसे घातक रसायनों सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता चलन भी समस्या बन रहा है।

अपको बता दें कि देश में नशी और नशीले पदार्थों की तस्करी ने एक बार फिर केन्द्र और राज्यों की सरकारों को स्तब्ध किया है। नशीले पदार्थों की यह तस्करी का बड़ा हिस्सा पड़ोसी देश पाकिस्तान के माध्यम से सीमा



सुनील कुमार महला

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत की एक तत्काल डिजिटल भुगतान प्रणाली है। सरल शब्दों में कहें तो यह वह माध्यम है, जिसके माध्यम से मोबाइल फोन से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत पैसे भेजें और प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां पाठकों को बताता चलूँ कि भारत में यूपीआई की 11 अप्रैल 2016 को तत्कालीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) गवर्नर डॉ. यू.राम लालन ने मुंबई में लॉन्च किया था। हालाँकि, आम लोगों के लिए यूपीआई सेवाएँ अगस्त 2016 से व्यापक रूप से उपलब्ध हुईं। इस साल यानी कि वर्ष 2026 में यूपीआई में अपनने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि यूपीआई ने भारत के डिजिटल भुगतान को पूरी तरह बदल दिया है। सच तो यह है यूपीआई आज भारत के दैनिक डिजिटल भुगतान तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज यूपीआई का उपयोग हर कहीं पर दुकानों और बाजारों में सामान खरीदने, रेस्तरां व होटलों के

आई@10: भुगतान की दुनिया में भारत का नया अध्याय

खेल चुकाने, ऑनलाइन खरीदारी, मोबाइल रिचार्ज, बिजली-पानी-गैस जैसे उपयोगिता बिलों के भुगतान, रेल-बस-विमान टिकट बुकिंग, स्कूल-कॉलेज की फीस, अस्पतालों में भुगतान वगैरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तुरंत पैसे भेजने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े कारोबारों तक प्रतिष्ठानों तक डिजिटल लेन-देन में यूपीआई का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। यानी आज यूपीआई भारत के दैनिक जीवन में नकद भुगतान के एक आसान, तेज और सुविधाजनक डिजिटल विकल्प के रूप में स्थापित हो चुका है। बहरहाल, यहां पाठकों को यह भी बताता चलूँ कि अन्य देशों की तुलना में भारत का यूपीआई डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में असाधारण पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। आजकड़े बताते हैं कि वर्ष 2026 में यूपीआई दुनिया के लगभग 49% रियल-टाइम भुगतान लेन-देन को संभाल रहा है, यानी दुनिया में होने वाले लगभग हर दो तत्काल डिजिटल भुगतानों में एक यूपीआई के माध्यम से होता है। भारत में इसकी मात्रा भी तेजी से बढ़ी है और वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई पर करीब 24,162 करोड़ लेन-देन हुए। मई 2026 में अकेले यूपीआई ने 23,201.93 मिलियन याना लगभग 2,320 करोड़ लेन-देन किए, जिनका कुल मूल्य करीब ₹.29.90 लाख करोड़ रहा। इस तुलना में भारत की रूपायित यह है कि यूपीआई केवल बड़े शहरों या बड़े कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, ग्रामीण उपभोक्ता और आम नागरिक तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई अब 11 देशों में भी उपलब्ध है और वैश्विक स्तर पर भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण बन चुका है। अन्य शब्दों में कहें तो

वर्ष 2016 में शुरू हुई यह व्यवस्था आज देश के कोने-कोने तक पहुंच चुकी है। पहले जहां डिजिटल भुगतान सीमित था, वहीं अब चायवाले, सब्जीवाले, छोटे दुकानदार और आम लोग भी आसानी से यूपीआई से पैसे ले-दे रहे हैं। एक दशक में यूपीआई लेन-देन में हुई भारी वृद्धि इसकी लोकप्रियता और लोगों के भरोसे को दिखाती है यूपीआई से बैंकिंग आसान, तेज और सुविधाजनक हुई है। लोगों को नकदी निकालने के लिए बैंक जाया या लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत कम हुई है। आज पलभर में ही दूर बैठे व्यक्ति को तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, नकदी कम खरचे से चोरी और लूट का जोखिम भी पड़ता है। डिजिटल भुगतान से लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में मदद मिली है यूपीआई की सफलता के पीछे डिजिटल इंडिया अभियान और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विकास भी महत्वपूर्ण रहा है। देश में मोबाइल और ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ने से डिजिटल भुगतान आम लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। यही कारण है कि दूसरे देश भी यूपीआई जैसी भारतीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था में रुचि दिखा रहे हैं हालांकि, अभी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। बैंक का सर्वर डाउन होना, अधिक ट्रैफिक के कारण भुगतान अटकना और गलती से गलत व्यक्ति को पैसे भेज देना जैसी समस्याएं लोगों के लिए परेशानी पैदा करती हैं। इन समस्याओं का स्थायी समाधान जरूरी है। कुल मिलाकर, यूपीआई केवल पैसे भेजने और लेने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल प्रगति और आत्मनिर्भर तकनीकी क्षमता का प्रतीक बन चुका है। दासनिर्भर इसकी क्षमता बढ़ती है। फ्रीक वन चुनौती को साम को इसकी क्षमता बढ़ती है। फ्रीक वन चुनौती को साम आदमी की जरूरतों से जोड़ा जाता है, तो



वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। सच तो यह है कि यूपीआई के दस वर्ष केवल किसी डिजिटल भुगतान प्रणाली की सफलता के दस वर्ष नहीं, बल्कि भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता और डिजिटल परिवर्तन की एक उल्लेखनीय यात्रा हैं। इसने भुगतान को सरल, स्वतंत्र और व्यापक बनाया तथा छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक को एक साझा डिजिटल मंच दिया। आज दुनिया के अनेक देश यूपीआई में रुचि ले रहे हैं और कई देशों में इसका उपयोग भी शुरू हो चुका है। यूपीआई ने साबित किया है कि भारत केवल डिजिटल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि दुनिया को बड़े पैमाने पर अपनाये योग्य डिजिटल समाधान देने वाला देश भी है। आने वाले वर्षों में इसकी सफलता का अगला पड़ाव केवल लेन-देन की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि सुरक्षित, समावेशी और वैश्विक डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और मजबूत करना होगा।

विरासत को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू : विश्व धरोहर सूची तक सारनाथ का गौरवपूर्ण सफर

बिहान भारत

दक्षिण कोरिया के बुसान में विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को शामिल किया गया है। इसके साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक और वैश्विक मान्यता मिली है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और ये उनके जीवन से जुड़े चार प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। इस उपलब्धि के साथ भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर संपत्तियों में संख्या 45 हो गई है। अब हमारा देश विश्व स्तर पर छठे और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। यह बौद्ध धर्म के जन्मस्थान के रूप में भारत की पहचान और उत्कृष्ट सावंभौमिक मूल्य की विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।

भारत की विरासत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि

विरासत अतीत की याद दिलाने से कहीं अधिक है। यह वर्तमान को आकार देती है और भविष्य का मार्गदर्शन करती है। यह उन कहानियों, परंपराओं और मूल्यों को दशाती है जिन्हें समुदाय संरक्षित करते हैं और पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत पहचान, ज्ञान और प्रेरणा के अपूरणीय स्रोत हैं। 25 जुलाई 2026 की शाम, दक्षिण कोरिया के बुसान में विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में, सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस उपलब्धि के साथ, भारत में अब यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 45 विश्व धरोहर संपत्तियां हो गई हैं। यह मान्यता विश्व धरोहर सूची में एक नई प्रविष्टि से कहीं अधिक है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न है, जो विविध परंपराओं, उल्लेखनीय वास्तुकला और एक लंबे इतिहास को संजोए हुए है। यह विश्व विरासत सम्मेलन की भावना को भी पुष्ट करती है, जो 196 देशों के दलों में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए उत्कृष्ट सावंभौमिक मूल्य के स्थानों की रक्षा करना चाहती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। ये मानवता के लिए असाधारण मूल्ेयों सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, संरक्षण और संरक्षण को बढ़ावा देता है। यह प्रतिबद्धता विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित समझौते में निहित है, जो 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था।

जुलाई 2026 तक, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 173 देशों की 1,273 संपत्तियां शामिल हैं, इनमें 991 सांस्कृतिक, 240 प्राकृतिक और 42 मिश्रित स्थल शामिल हैं। अक्टूबर 2024 तक, 196 सदस्य देशों ने विश्व धरोहर समझौते को मंजूरी दी है, इससे यह संयुक्त राष्ट्र की किसी भी एजेंसी द्वारा सबसे ज्यादा सारे और माने जाने वाले समझौतों में से एक बन गया है। राष्ट्रीय सीमाओं से परे तक फैला हुआ विश्व विरासत का विचार अद्वितीय है। ये स्थल अलग-अलग देशों के क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं फिर भी इनका महत्व पूरी मानवता का है। इन्हें एक साझा विरासत के रूप में पहचाना जाता है और इन-?हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाए रखने के लिए सामूहिक देखभाल और सुरक्षा मिलनी चाहिए।

सारनाथ की कहानी

सारनाथ बौद्ध परंपरा में विशेष स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित, यह बौद्ध तीर्थयात्रा के चार प्रमुख स्थलों में से एक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर शिलालेख में दो जुड़े हुए घटक शामिल हैं: चौखंडी स्तूप और सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक परिसर में धमेक स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, मूलगंधकुटी विहार, अशोक स्तंभ और कई अन्य प्राचीन अवशेष शामिल हैं। साथ में, वे इस प्राचीन स्थल के ऐतिहासिक परिदृश्य को संरक्षित करते हैं। बौद्ध परंपरा में ऋषिपतन, इषिपतन और मुगदेव के रूप में जाना जाता है, सारनाथ वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपना पहला उपदेश दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन या रप्रगति के पथ पर नया मोड़र के रूप में जाना जाने वाला यह उपदेश बौद्ध संघ की शुरुआत और आर्य अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों की स्थापना की पहचान करता है। सदियों से, सारनाथ का विकास शाही, मठवासी और सामान्य संरक्षण के माध्यम

से हुआ। बुद्ध के पहले उपदेश और उनके पहले पांच शिष्यों के साथ उनकी मुलाकात से जुड़े स्थान के चारों ओर कई स्तूपों, मंदिरों और विहारों का निर्माण किया गया था। यह स्थल लगभग सोलह शताब्दियों के निरंतर विकास को दर्शाता है। इसके स्मारक चौथी-तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य काल से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक के हैं, जब सारनाथ का पतन हो गया और नष्ट हो गया। 18 वीं शताब्दी में इसकी पुनर्खोज तक यह जगह अनदेखी रही।

मान्यता का मार्ग

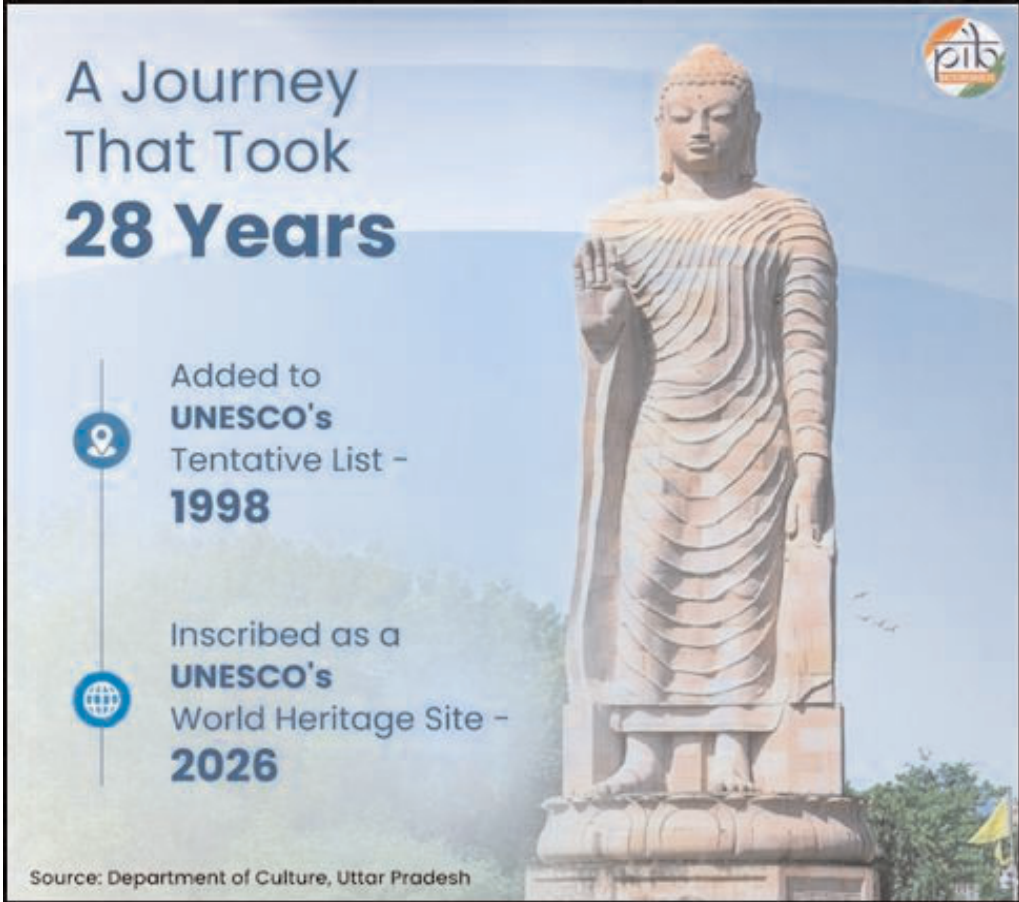
सारनाथ की विश्व धरोहर मान्यता की यात्रा एक लंबी और सावधानीपूर्वक प्रक्रिया रही है। इस प्राचीन स्थल को 1998 में भारत की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। इसके शिलालेख का प्रस्ताव जनवरी 2025 में विश्व धरोहर समिति द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद अठारह महीने की लंबी प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें यूनेस्को के सलाहकार निकायों के साथ तकनीकी बैठकें और प्रस्तावित संपत्ति की योग्यता की समीक्षा करने के लिए आईसीओएमओएस द्वारा एक मूल्यांकन मिशन शामिल था। आईसीओएमओएस, यूनेस्को के सलाहकार निकायों में से एक के रूप में कार्य करते हुए, शिलालेख के लिए प्रस्तावित सांस्कृतिक और मिश्रित संपत्तियों का मूल्यांकन प्रदान करता है। इस प्रक्रिया का समापन दक्षिण कोरिया के बुसान में विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के साथ हुआ। सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची (विश्व धरोहर सम्मेलन के ढांचे के तहत) के मानदंड (iii) और (vi) के तहत नामित किया गया था। मानदंड (iii) बौद्ध तीर्थयात्रा के चार प्रमुख स्थलों में से एक के रूप में सारनाथ के स्थायी आध्यात्मिक महत्व को मान्यता देता है। यह सदियों से साइट पर निर्मित और पुनर्निर्माण की गई कई धार्मिक इमारतों और स्मारकों में परिलक्षित होता है। मानदंड (vi) बुद्ध के जीवन में होने वाली घटनाओं के साथ सारनाथ के प्रत्यक्ष और मूर्त जुड़ाव को पहचानता है जो बौद्ध समुदाय के लिए उत्कृष्ट महत्व रखते हैं। इनमें उनका पहला उपदेश और बोधगया में बोधि (ज्ञान) प्राप्त करने के बाद उनके पहले शिष्यों के साथ उनकी भेंट शामिल है। सदियों से सारनाथ में निर्मित कई संरचनाएं इन घटनाओं के निरंतर महत्व, बुद्ध की शिक्षाओं और त्रिरत्न की अवधारणा को दर्शाती हैं। शिलालेख विश्व धरोहर सम्मेलन के व्यापक उद्देश्य को भी दर्शाता है। यूनेस्को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उत्कृष्ट सावंभौमिक मूल्य की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना चाहता है।

सारनाथ: शांति की वैश्विक विरासत

सारनाथ का एक पुरातात्विक स्थल से कहीं अधिक महत्व है। यह जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, मंगोलिया और कई अन्य देशों के बौद्धों के लिए एक वैश्विक तीर्थ स्थल बना हुआ है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक के रूप में, यह बौद्ध धर्म के जन्मस्थान के रूप में भारत की पहचान को मजबूत करता है और बौद्ध देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बंधों और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करता है। सारनाथ के शिलालेख के साथ, बुद्ध के जीवन से जुड़े चार प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से तीन अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। इनमें नेपाल में लुंबिनी, बिहार में बोधगया में महाबोधि मंदिर और उत्तर प्रदेश में सारनाथ शामिल हैं। वे भारत में सांची, नालंदा और अजंता, श्रीलंका में अनुराधापुरा, बांग्लादेश में पहाड़पुर और वर्तमान पाकिस्तान में तक्षशिला और तख्त-ए-बाही सहित अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हो गए हैं। यह मान्यता सारनाथ के उत्कृष्ट सावंभौमिक मूल्य की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करती है। सरकार पर्यटन का स्थायी प्रबंधन करेगी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए साइट की प्रामाणिकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बफर जोन के भीतर अनियोजित विकास को रोकेगी।

भारत की विरासत की सफलता को सक्षम करना

प्रत्येक सफल नामांकन के पीछे वर्षों का संस्थागत आधार होता है। विश्व धरोहर



संपत्तियों के प्रति भारत का दृष्टिकोण केन्द्रीय एजेंसियों, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच घनिष्ठ समन्वय पर निर्भर करता है।

संस्कृति मंत्रालय

संस्कृति मंत्रालय सांस्कृतिक मामलों पर यूनेस्को के साथ भारत के सम्बंध का नेतृत्व करता है। यह यूनेस्को के सांस्कृतिक सम्मेलनों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को लागू करता है और विश्व धरोहर स्थलों और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के लिए नामांकन का समन्वय करता है। मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय विरासत संरक्षण मानकों को भी बढ़ावा देता है और यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) भारत सरकार की ओर से विश्व विरासत से सम्बंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी है। यह 28 विश्व धरोहर संपत्तियों सहित 3688 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव करता है। इसके कार्य में पेयजल, शौचालय, रास्ते और भूमिर्माण जैसी आंगतुक सुविधाएं प्रदान करने के अलावा प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और पुरावशेष और कला निधि अधिनियम, 1972 नामक दो कानूनों को लागू करना भी शामिल है। प्रत्येक स्मारक की आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नियमित रूप से संरक्षण और रखरखाव किया जाता है।

भारत की विश्व धरोहर सूची में विस्तार

हमारी विरासत सिर्फ पत्थरों, लिपियों या खंडहरों तक सीमित नहीं है। यह मंदिर की दीवार की प्रत्येक फुसफुसाहट में है, प्राचीन किलों की नक्काशियों और पीढ़ियों से चले आ रहे हर लोक गीत में यह झलकती है।

यह भारत की सभ्यता की कहानी बताती है और देश की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को दर्शाती है।

देश और विश्व धरोहर स्थल (जुलाई 2026 तक)

इटली 62,चीन 61 फ्रांस 56 जर्मनी 55 स्पेन 50 भारत 45 मेक्सिको 36 यूनाइटेड किंगडम 35 रूस 33 आज, भारत 45 यूनेस्को विश्व धरोहर संपत्तियों का घर है, इसमें 37 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं। यह देश को विश्व स्तर पर छठे और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रखता है। भारत की पहली प्रविष्टियां एक ही वर्ष में आईं। ताजमहल, एलोरा गुफाओं और अजंता गुफाओं के साथ आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया था, इससे एक सूची खुल गई थी जो तब से किलों, मंदिरों, गुफाओं, रेलवे, बावड़ियों, नियोजित शहरों और राष्ट्रीय उद्यानों को कवर करने के लिए विकसित हुई है। पिछले साल, पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47 वें सत्र में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया था। बुसान में 48वें सत्र में इस वर्ष सारनाथ के शामिल होने के साथ, भारत की संख्या अब 45 संपत्तियों तक पहुंच गई है, इससे देश विश्व स्तर पर छठे स्थान पर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। भारत की अस्थायी सूची भी बढ़ कर अब 69 संपत्तियों तक पहुंच गई है। यह भविष्य में किसी भी विश्व धरोहर नामांकन के लिए अनिवार्य पहला कदम है।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

भारत ने अपनी विशाल सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा, पुनर्स्थापना

और संवर्धन के लिए कई सार्थक कदम उठाए हैं। ये पहल देश की कालातीत परंपराओं और ऐतिहासिक खजानों की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। संरक्षण, डिजिटलीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जनभागीदारी में केन्द्रित प्रयासों के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत की रक्षा की जा रही है।

पुरावशेषों की पुनर्प्राप्ति

भारत में 2014 के बाद से 656 सहित कुल 669 पुरावशेष वापस लाए गए हैं। इस प्रयास में संस्कृति मंत्रालय, एएसआई, भारतीय मिशन और प्रवर्तन एजेंसियां शामिल हैं। हाल ही में, 657 भारतीय कला वस्तुओं को अमेरिकी कानून प्रवर्तन आई। ताजमहल, एलोरा गुफाओं और अजंता गुफाओं के साथ आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया था, इससे एक सूची खुल गई थी जो तब से किलों, मंदिरों, गुफाओं, रेलवे, बावड़ियों, नियोजित शहरों और राष्ट्रीय उद्यानों को कवर करने के लिए विकसित हुई है। पिछले साल, पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47 वें सत्र में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया था। बुसान में 48वें सत्र में इस वर्ष सारनाथ के शामिल होने के साथ, भारत की संख्या अब 45 संपत्तियों तक पहुंच गई है, इससे देश विश्व स्तर पर छठे स्थान पर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। भारत की अस्थायी सूची भी बढ़ कर अब 69 संपत्तियों तक पहुंच गई है। यह भविष्य में किसी भी विश्व धरोहर नामांकन के लिए अनिवार्य पहला कदम है।

विरासत अपनाएं

सितंबर 2017 में शुरू और सितंबर 2023 में नया रूप वाला एड्रॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और समाजों के साथ सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। यह राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों में आंगतुक-अनुकूल सुविधाओं को विकसित करने और बनाए रखने पर केन्द्रित है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और अन्य योगदानों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य आंगतुक अनुभव को बेहतर बनाना है। मार्च 2026 तक, 'अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0' प्रोग्राम के तहत कुल 30 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह कार्यक्रम पहले से ही बेहतर साइट प्रबंधन और बढ़ी हुई सार्वजनिक भागीदारी के संदर्भ में दृश्यमान परिणामों का प्रदर्शन कर रहा है। यह गोट लिए गए स्मारकों में आंगतुकों की मजबूत भागीदारी में

भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची:

वर्ष	स्थल/राज्य	केन्द्र शासितप्रदेश	श्रेणी
1983 : आगरा का किला	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	सांस्कृतिक
1983 : अजंता की गुफाएं	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	सांस्कृतिक
1983 : एलोरा की गुफाएं	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	सांस्कृतिक
1983 : ताजमहल	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	सांस्कृतिक
1984 : कोणार्क का सूर्य मंदिर	ओडिशा,	ओडिशा,	सांस्कृतिक
1984 : महाबलीपुरम के स्मारक समूह	तमिलनाडु	तमिलनाडु	सांस्कृतिक
1985 : काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम	असम	प्राकृतिक
1985 : केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान	राजस्थान	राजस्थान	प्राकृतिक
1985 : मानस वन्यजीव अभयारण्य	असम	असम	प्राकृतिक
1986 : खजुराहो स्मारक समूह	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	सांस्कृतिक
1986 : फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	सांस्कृतिक
1986 : गोवा के चर्च और कॉन्वेंट	गोवा	गोवा	सांस्कृतिक
1986 : हम्पी के स्मारक समूह	कर्नाटक	कर्नाटक	सांस्कृतिक
1987 : सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	प्राकृतिक
1987 : एलिफेंटा की गुफाएं	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	सांस्कृतिक
1987 : पट्टदकल के स्मारक समूह	कर्नाटक	कर्नाटक	सांस्कृतिक
1987, 2004 : महान जीवित चोल मंदिर	तमिलनाडु	तमिलनाडु	सांस्कृतिक
1988, 2005 : नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान	उत्तराखंड	उत्तराखंड	प्राकृतिक
1989 : सांची के बौद्ध स्मारक	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	सांस्कृतिक
1993 : हुमार्ग का मकबरा, दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली	सांस्कृतिक
1993 : कुतुब मीनार और उसके स्मारक, दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली	सांस्कृतिक
1999, 2005, 2008 : भारत की पर्वतीय रेलागड़ियां पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश	पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश	पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश	सांस्कृतिक
2002 : बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर	बिहार	बिहार	सांस्कृतिक
2003 : भीमबेटका की गुफाएं (रॉक शैल्टर)	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	सांस्कृतिक
2004 : चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क	गुजरात	गुजरात	सांस्कृतिक
2004 : छत्रपति शिवाजी टर्मिनस	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	सांस्कृतिक
2007 : लाल किला परिसर	दिल्ली	दिल्ली	सांस्कृतिक
2010 : जंतर-मंतर, जयपुर	राजस्थान	राजस्थान	सांस्कृतिक
2012 : पश्चिमी घाट	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु	प्राकृतिक
2013 : राजस्थान के पहाड़ी किले	राजस्थान	राजस्थान	सांस्कृतिक
2014 : ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	प्राकृतिक
2014 : पाटन में रानी-की-वाव (रानी की बावड़ी)	गुजरात	गुजरात	सांस्कृतिक
2016 : नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल	बिहार	बिहार	सांस्कृतिक
2016 : कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान	सिक्किम	सिक्किम	मिश्रित
2016 : ले कोर्बुसिए का वास्तुशिल्प कार्य	चंडीगढ़	चंडीगढ़	सांस्कृतिक
2017 : अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर	गुजरात	गुजरात	सांस्कृतिक
2018 : मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको समूह	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	सांस्कृतिक
2019 : जयपुर शहर	राजस्थान	राजस्थान	सांस्कृतिक
2021 : धोलावीरा : एक हड़प्पा शहर	गुजरात	गुजरात	सांस्कृतिक
2021 : काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर	तेलंगाना	तेलंगाना	सांस्कृतिक
2023 : होयसल के पवित्र मंदिर समूह	कर्नाटक	कर्नाटक	सांस्कृतिक
2023 : शान्तिनिकेतन	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	सांस्कृतिक
2024 : मोइदमस ज़ाहोम राजवंश की टीलेनुमा समाधि प्रणाली	असम	असम	सांस्कृतिक
2025 : भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य	महाराष्ट्र, तमिलनाडु	महाराष्ट्र, तमिलनाडु	सांस्कृतिक
2026 : सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	सांस्कृतिक

परिलक्षित होता है, इससे सामूहिक रूप से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 13.59 मिलियन आंगतुकों की उपस्थिति दर्ज हुई है। ये आंकड़े आंगतुकों की मजबूत रुचि को दर्शाते हैं और सुझाव देते हैं कि कार्यक्रम के तहत बेहतर सुविधाएं, सेवाएं और ऑन-साइट सुविधा आंगतुकों के बेहतर अनुभव और गोट लिए गए विरासत स्थलों पर उच्च जुड़ाव में योगदान दे रही हैं।

ज्ञान भारतम मिशन

2025 में शुरू किया गया ज्ञान भारतम मिशन, सरकार की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करना, डिजिटल बनाना और प्रसारित करना है। यह पांडुलिपियों में दर्ज प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करने पर केन्द्रित है। यह उन्हें डिजिटल रिपॉजिटरी और संरक्षण नेटवर्क के माध्यम से अनुसंधान और सार्वजनिक जुड़ाव के लिए भी सुलभ बनाता है। यह पहल इन दुर्लभ पांडुलिपियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे विश्व स्तर पर सुलभ हों। इसके अतिरिक्त, पांडुलिपियों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस पहचानने, दस्तावेजीकरण करने और बनाने के लिए मार्च 2026 में राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण भी शुरू किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान, 1.19 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों की सूचना मिली है। देश भर में उपलब्ध डिजिटल पांडुलिपियों की कुल संख्या 8 लाख से अधिक है, इनमें से 4.40 लाख से अधिक पांडुलिपियां वर्तमान में ज्ञान भारतम पोर्टल पर सार्वजनिक पहुंच के लिए उपलब्ध हैं। ये राज्यवार सुलभ हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भी अभिलेख पटल के माध्यम से अभिलेखीय अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर रहा है। फरवरी 2026 तक, पोर्टल ने 18.23 करोड़ पृष्ठों, 0.73 करोड़ संदर्भ मौडिया और 0.38 करोड़ डिजिटल रिकॉर्ड की मेजबानी की।

दस्तावेजीकरण करने और बनाने के लिए मार्च 2026 में राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण भी शुरू किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान, 1.19 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों की सूचना मिली है। देश भर में उपलब्ध डिजिटल पांडुलिपियों की कुल संख्या 8 लाख से अधिक है, इनमें से 4.40 लाख से अधिक पांडुलिपियां वर्तमान में ज्ञान भारतम पोर्टल पर सार्वजनिक पहुंच के लिए उपलब्ध हैं। ये राज्यवार सुलभ हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भी अभिलेख पटल के माध्यम से अभिलेखीय अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर रहा है। फरवरी 2026 तक, पोर्टल ने 18.23 करोड़ पृष्ठों, 0.73 करोड़ संदर्भ मौडिया और 0.38 करोड़ डिजिटल रिकॉर्ड की मेजबानी की।

स्मारकों और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन कार्यान्वित किया जाता है। यह भारत की निर्मित विरासत और पुरावशेषों का एक विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस बनाकर संरक्षण सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिशन का उद्देश्य सीधे संरक्षण कार्य की योजना, प्राथमिकता और निगरानी की सूचना के साथ-साथ जानकारी देने के लिए देश में सभी स्मारकों और पुरावशेषों की एक सूची का दस्तावेजीकरण और निर्माण करना है। मार्च 2026 तक, एनएमएमए ने 1.84 लाख स्मारकों का दस्तावेजीकरण किया है, इसमें निर्मित विरासत और स्थल शामिल हैं। पूरे भारत में 17.20 लाख पुरावशेषों का भी दस्तावेजीकरण किया गया है।

अतीत का संरक्षण, भविष्य को दिशा देना

भारत की सांस्कृतिक विरासत एक जीवंत विरासत है। यह पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती है, शिक्षित करती है और जोड़ती रहती है। सारनाथ का शिलालेख शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सतत विकास में असाधारण मूल्य के स्थानों के संरक्षण के लिए देश की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, अपनी विरासत की रक्षा करने, अपनी सभ्यतागत विरासत को संरक्षित करने और इसे दुनिया के साथ साझा करने पर केन्द्रित रहेगा।

हिमाचल में भूकंप, किचन में रखे वर्तन गिरे, सुबह-सुबह लगे झटके लोग घरों से निकले

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल की राजधानी शिमला सहित आस पास के शहरों में आए भूकंप ने लोगों को डरा दिया। घरों की किचन में रखे वर्तन गिरने लगे। जब तक लोग समझ पाते तब तक झटके लगने लगे। लोग डर के चलते घरों से बाहर निकले तब पता चला कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। सुबह 5 बजकर 46 मिनट और 50 सेकंड पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 दर्ज की गई। इसका केंद्र शिमला से करीब 66 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण दिशा में, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे जुबल-कोटखाई की तरफ था। यह झटका लगभग तीन सेकंड तक महसूस किया गया, जिसके दौरान धरती डोलने पर कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, उस समय कई लोग नींद में थे, जिस वजह से उन्हें इसका पता नहीं चल पाया। कुछ नागरिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से तेज झटका लगने की जानकारी साझा की। शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी के कई अन्य क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके अनुभव किए गए। गनीमत यह रही कि इस घटना में फिलहाल किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्यों में आता है, जिसमें शिमला और मंडी जैसे जिले जोन-4 और जोन-5 के अंतर्गत आते हैं। सामान्य तौर पर 5.0 से कम तीव्रता वाले भूकंपों से बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावना कम होती है। इससे पहले हाल ही में चंबा और कांगड़ा जिलों में भी भूकंप के झटके दर्ज किए जा चुके हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

गोवा कैबिनेट का ऐतिहासिक कदम : गैर-कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद की सजा का प्रस्ताव

पणजी (एजेंसी)। गोवा कैबिनेट ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। यह विधेयक जबरन, दबाव, लालच, धोखाधड़ी या शायदी के मकसद से किए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों का है। प्रस्तावित कानून के तहत इसतरह के मामलों में दोषियों को उम्रकैद तक की सजा, न्यूनतम 50 हजार रुपये का जुर्माना और पीड़ितों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। विधेयक प्रावधान करता है कि यदि कोई शायदी केवल गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई हो, तब उस शायदी को अमान्य घोषित किया जा सकता है। धर्मांतरण में शामिल दोषियों को कम से कम तीन साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। यदि धर्मांतरण का शिकार कोई नाबालिग, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तब यह सजा 5 से 14 साल की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ सकती है। मुख्य सचिव वी. कंडावेलू ने इस कानून के उद्देश्य पर कहा कि इसका मकसद कमजोर और भोले-भाले लोगों को अनुचित तरीकों से होने वाले धर्मांतरण से बचाना है। प्रस्तावित कानून के अनुसार, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा, जबकि धर्मांतरण समारोह आयोजित करने वाले व्यक्ति को रस्म से एक महीने पहले जानकारी देनी होगी।

कंगना के पलटवार से सन्न बाबा रामदेव : जवानी पर सवाल उठाना पड़ा भारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजनीति और मनोरंजन की दुनिया में अपने बेबाक बयानों से सुर्खियां बटोरने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत और योगगुरु बाबा रामदेव के बीच छिड़ा जुवानी जंग अब व्यक्तिगत हमलों में बदल गया है। कंगना के विवादित जनरेशन गटर बयान से शुरू हुआ यह मामला, रामदेव द्वारा उनकी जवानी और अतीत पर सवाल उठाने के बाद तीखी व्यक्तिगत पलटवार में बदल गया। कंगना के करारे जवाब से सन्न हुए रामदेव को आश्चर्यचकर यह कहना पड़ा कि वह विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहें। दरअसल, जंतर-मंतर पर युवाओं को जनरेशन गटर कहने पर उठे विवाद के बीच, जब बाबा से कंगना के बयान पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने अभिनेत्री-सांसद पर हमला बोल दिया। रामदेव ने कहा था, ‘उनका बचपन कैसा था? उनकी जवानी कैसी थी? उनके पिछले काम कैसे थे?’ में इसतरह के लोगों पर बात नहीं करना चाहता। युवाओं को जनरेशन गटर कहना विकृत मानसिकता की निशानी है।’ रामदेव के इन्हें निजी टिप्पणियों पर सांसद कंगना ने तत्काल और तीखा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ‘बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिवास्वप्न मत देखिए। अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही कुछ भी मान सकते हैं। कम से कम मुझे झूठे या भ्रामक प्रभावकारिता दावों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी।’ कंगना यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने रामदेव को वरिष्ठ पर उपदेश देने से साफ मना किया और दो चरक कहा, ‘मुझे कैरेक्टर लेसन मत दीजिए। तुमसे तब उहूत ज्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर।’ नो फॉर्गट डिटेक्टेड हिस्पर ।’ यह पलटवार पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के उस मामले की ओर इशारा था, जहां 2024 में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी थी।

कोर्ट के फैसले पर भड़के ओवैसी ने कहा- ‘हमारा धर्म, हम तय करेंगे’

बोले- जज तय नहीं कर सकते कि इस्लाम में क्या जरूरी है; फैसले को अनुच्छेद 19 और 25 के खिलाफ बताया

हैदराबाद, एजेंसी।

स्कुलों में हिजाब या हेडस्कार्फ पहनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह तय करना न्यायाधीशों का काम नहीं है कि इस्लाम में कौन-सी धार्मिक प्रथा जरूरी है और कौन-सी नहीं। ओवैसी ने इसे धर्म पर हमला बताते हुए कहा, ‘यह हमारा धर्म है और हम तय करेंगे कि क्या जरूरी है। जज कौन होते हैं यह तय करने वाले?’ सांसद ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों पर विचार कर रहा है। ऐसे में उनका कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मुद्दे पर फैसला नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट का आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के खिलाफ है। ओवैसी ने स्कूल छात्रा की हिजाब पहनने



की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह उसकी पसंद और निजता का मामला है। उन्होंने कहा, ‘वह हिजाब अपने सिर पर पहन रही है, न कि अपने दिमाग पर।’ उन्होंने दावा किया कि ऐसे फैसलों का मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ सकता है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम छात्राओं के स्कूल नामांकन को लेकर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि ऐसे कदम उनकी शिक्षा में बाधा डाल सकते हैं।

तथा है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला?...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को एक मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल प्रयागराज के एक निजी स्कूल की छात्रा ने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रा हाई स्कूल पास करने के बाद उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में दाखिला लेना चाहती थी। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने कहा कि किसी छात्र को शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में अपनी पसंद के अनुसार बदलाव करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह दलील भी स्वीकार नहीं की कि सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मुद्दे पर जिन मामलों में विभिन्न हाईकोर्ट ने विचार किया है, उनमें यह राय सामने आई है कि महिलाओं के लिए सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लामी आस्था का ऐसा अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिसके बिना धार्मिक आस्था खतरे में पड़ जाए।

लोकसभा स्पीकर ने टीएमसी से 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर की थी। इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन सांसदों को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। यह घटनाक्रम तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी की मांगेला रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय्यमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने सांसदों को नोटिस जारी किया और स्पीकर के पास आचरण के लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द विचार करने को कहा है।

लोकसभा स्पीकर और सेक्रेटरी जनरल को ओर से पेश सॉलिसिट जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत टीएमसी द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर उन 20 बिरला ने उन सांसदों को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। यह घटनाक्रम तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी की मांगेला रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय्यमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने सांसदों को नोटिस जारी किया और स्पीकर के पास आचरण के लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द विचार करने को कहा है।

पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी अमेरिका को की थी लीक पूर्व सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी।

पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान ने पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि इस ऑपरेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की ओर से अमेरिका को लीक की गई होगी। पूर्व सीडीएस ने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर पूरी तरह द्विपक्षीय बातचीत हुई थी और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। ऐसे में उन्होंने इस बात पर गहरी हेरानी जताई कि भारत की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कैसे कर दिया। पूर्व सीडीएस ने बताया कि गत वर्ष 29 अप्रैल को आतंकवादी ठिकानों को सटीक निशाना बनाने का अहम फैसला लिया गया था और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सेना पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। संघर्ष विराम की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) के बीच आपसी सहमति से समय तय किया गया था। फोन पर



था और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सेना पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। संघर्ष विराम की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) के बीच आपसी सहमति से समय तय किया गया था। फोन पर

बातचीत के बाद शाम पांच बजे का समय निर्धारित हुआ था, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि सीजफायर केवल दो सैन्य अधिकारियों के बीच की आपसी समझ का परिणाम था। जब उनसे यह सवाल किया गया कि यह गोपनीय जानकारी अमेरिका तक कैसे पहुंची, तो उन्होंने साफ

शब्दों में कहा कि यह सूचना भारतीय पक्ष की तरफ से बिल्कुल लीक नहीं की गई थी। उन्होंने अंदेशा जताया कि यह जानकारी निश्चित तौर पर दूसरे पक्ष यानी पाकिस्तान की तरफ से ही लीक हुई होगी। इसके अलावा, पूर्व सीडीएस ने किराना हिल्स पर किए गए हमलों की अटकलों पर भी विराम लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों वाले क्षेत्र किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया गया था। उन्होंने समझाया कि हमलों से पहले सरोगोधा क्षेत्र में कई ड्रोन भेजे गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य वहां के रडार का पता लगाना था। हवा में लंबे समय तक मंडराने के बाद यदि इन ड्रोनो को कोई लक्षित स्थान नहीं मिलता है, तो वे नीचे उतरकर टकरा जाते हैं। संभवतः इसी प्रक्रिया के दौरान कोई ड्रोन किराना पहाड़ियों से टकरा गया होगा, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने गलत तरीके से प्रचारित किया था।

5 सितंबर को इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च का ऐलान

सीजेपी के नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली, एजेंसी।

जेन-जी से जुड़े एक हालिया कान्वलेव में कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों मुख्य चेहरे अभिजीत दीपक, आशुतोष रांका और सौरव दास शामिल हुए। इस दौरान जब अभिजीत दीपक से सवाल किया गया कि क्या वे दिल्ली केवल बवाल मचाने आते हैं और उन्होंने फिर से मार्च का ऐलान क्यों किया है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उनका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाना है जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। दीपक ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के लिए एक करोड़ रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि सांसद और विधायकों की खरीद-फरोख्त में 50 से 100 करोड़ रुपये आसानी से खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों की मदद करने में कंजूसी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी दूसरी प्रमुख मांग छात्रों पर दर्ज की गई एफआईआर को तुरंत वापस लेने की है, क्योंकि प्रदर्शन करने वाले छात्र अपने शिक्षा से जुड़े अधिकार गंवा रहे थे, न कि किसी से वोट। कार्यक्रम के दौरान घोषणा करते हुए दीपक ने बताया कि आगामी 5 सितंबर को इंडिया गेट 1.0



के तहत वे इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक शांति मार्च निकालेंगे। उन्होंने बताया कि वे आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवार से मिले थे, जिनके पिता को बेंटी की मौत के सदमे में पैरालिसिस और हाट अटैक आ गया था। उस परिवार ने अपनी बेंटी को डॉक्टर बनाने के लिए 15 लाख रुपये का कर्ज लिया था और अब वे गहरे आर्थिक संकट में हैं। चर्चा के दौरान आशुतोष रांका से जयपुर में हुई घटनाओं और सुरक्षा चिंताओं को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे वोट मांगने नहीं बल्कि मांग रहे थे, न कि किसी से वोट। कार्यक्रम के दौरान घोषणा करते हुए दीपक ने बताया कि आगामी 5 सितंबर को इंडिया गेट 1.0

राजधानी के पास स्कूल भैंसों के तबले में चल रहे हैं, तो यह शर्मानाक है। हिंसा के डर से जुड़े सवाल पर अभिजीत दीपक ने तंज करते हुए कहा कि वे और रांका पहले ही पुलिस या विरोध के दौरान पिट चुके हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो वे आगे भी प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार हैं। सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के रवैये पर बात करते हुए कहा कि मंत्रियों के वादों के बावजूद युवाओं के साथ विश्वासघात हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर की सूची मांगने और केंद्र सरकार के वकीलों द्वारा इस पर स्पष्ट प्रतिबद्धता न दिखाने के कारण उन्हें युवाओं के हित में यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है।

अन्नपूर्णा योजना पर ममता के सवाल, सुवेंदु ने आंकड़ों के साथ दिया जवाब

कोलकाता, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच जुवानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार विवाद की वजह अन्नपूर्णा योजना को लेकर उठे सवाल हैं। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर योजना के लाभ को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद सुवेंदु अधिकारी ने आंकड़े पेश करते हुए उनके आरोपों का जवाब दिया। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने राज्य की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। ममता बनर्जी ने सोमवार दोपहर सोशल मीडिया लाइव के दौरान अन्नपूर्णा योजना को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने

दावा किया कि कुछ महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और आरोप लगाया कि लाभार्थियों के चयन में जाति को आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने की अपील की, जिन्हें कथित तौर पर योजना का लाभ नहीं मिला है। ममता ने कहा कि वह लोगों के साथ पहले भी खड़ी थीं और आगे भी रहेंगी। सुवेंदु ने बलाए लाभार्थियों के आंकड़े ममता के आरोपों पर सुवेंदु अधिकारी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अन्नपूर्णा योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 45 लाख 64 हजार 472 लाभार्थियों को मिला है। उनके मुताबिक, इनमें करीब 19 लाख 20 हजार मुस्लिम लाभार्थी भी शामिल हैं। उन्होंने दावा

किया कि योजना का लाभ देते समय जाति और धर्म को आधार नहीं बनाया जाता। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों की करीब एक लाख महिलाओं को योजना के तहत लाभ मिलने का भी दावा किया। नंदीग्राम के एक ब्लॉक का उदाहरण देते हुए अधिकारी ने कहा कि वहां दो हिंदू और 52 मुस्लिम परिवारों को आवास के लिए आर्थिक सहायता दी गई। उनके मुताबिक, सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। सुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि अन्नपूर्णा योजना को लेकर सरकार के पास करीब 4.5 लाख शिकायतें पहुंची हैं। इनमें योजना का लाभ मिलने और लाभ से वंचित रहने, दोनों तरह की शिकायतें शामिल हैं। उन्होंने सवाल

उठाया कि यदि योजना का उद्देश्य सभी पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना था तो शुरुआत में इसे 25 से 60 वर्ष की आयु सीमा तक क्यों सीमित किया गया। उन्होंने बताया कि शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। आंकड़े गिनाने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के सोशल मीडिया लाइव को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ममता दोपहर में सोशल मीडिया पर ही रहती हैं और उन्हें सड़कों पर निकलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ममता की हालिया राजनीतिक गतिविधियों पर भी कटाक्ष किया और बारहपूर तथा हलीशहर में उनके कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए खेल के उदाहरण दिए।



कर्नाटक : मंत्री नागेंद्र ने 89 करोड़ रुपये के कथित घोटाले पर इस्तीफे की पेशकश की



बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित 89 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले के आरोपों के बीच, राज्य के योजना एवं सांख्यिकी मंत्री बी.नागेंद्र ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। विपक्षी भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) ने मामले को लेकर डीके शिवकुमार सरकार पर भारी दबाव बनाया हुआ था। विपक्षी भाजपा ने नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान लगातार विरोध प्रदर्शन किए, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फीडमार्क से विधानसभा का घेराव करने का भी प्रयास किया, जिसके बाद विपक्ष के नेता आर. अशोक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। विपक्ष का आरोप था कि कथित घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेकर नागेंद्र को तत्काल पद से हटना चाहिए। भाजपा ने तर्क दिया कि करीब 89 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच के दौरान संबंधित मंत्री का पद पर बने रहना उचित नहीं है। लगातार विरोध प्रदर्शनों, विधानसभा में हंगामे और बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण ही नागेंद्र ने यह फैसला लिया। नागेंद्र की इस्तीफे की पेशकश को विपक्ष के निरंतर दबाव का परिणाम माना जा रहा है। हालांकि, उनका इस्तीफा स्वीकार करने का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेतृत्व पर निर्भर है। विधानसभा सत्र भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन वाल्मीकि निगम के कथित घोटाले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव अभी भी जारी है।

सोने-चांदी की कीमतों में उछाल



नई दिल्ली ।

घरेलू बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया। अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड की अप्रत्याशित रूप से अधिक बायबैक की घोषणा के बाद से ही सोने की कीमतों तीन महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गयीं। वैश्विक बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर सोना 4,700 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया। चांदी भी 69 डॉलर प्रति औंस के आसपास बनी हुई है। इस तेजी से निवेशकों का ध्यान एक बार फिर सुरक्षित निवेश मानी जाने वाली इन धातुओं की ओर बढ़ा है।

वहीं घरेलू बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने और चांदी की वायदा कीमतों में उछाल देखा तेजी रही। एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 1,63,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब, जबकि चांदी का भाव 2,45,700 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब कारोबार कर रहा था।

एमसीएक्स पर सोने के बेंचमार्क अक्टूबर अनुबंध की शुरुआत तेजी के साथ हुई। यह 320 रुपये की बढ़त के साथ 1,63,202 रुपये के भाव पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,62,882 रुपये था। वर्तमान समय में, यह अनुबंध 254 रुपये की तेजी के साथ 1,63,136 रुपये के भाव पर कारीबार कर रहा था। दिन के कारोबार के दौरान ये 1,63,202 रुपये के उच्च स्तर और 1,62,021 रुपये के निचले स्तर पर पहुंचा।

इसी प्रकार चांदी के वायदा भाव में भी बड़ी तेजी रही। एमसीएक्स पर सितंबर अनुबंध 1,456 रुपये की बड़ी बढ़त साथ 2,45,583 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव 2,44,127 रुपये था। दिन के दौरान इसका उच्चतम स्तर 2,46,180 रुपये और न्यूनतम स्तर 2,45,430 रुपये रहा। चांदी के वायदा भाव इस साल 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम का ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर भी सोने चांदी के वायदा भाव में सकारात्मक रुख जारी है। सोने का भाव 4,715.70 डॉलर प्रति औंस पर खुला और खबर् लिखे जाने तक 10.90 डॉलर की तेजी के साथ 4,705.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इसका पिछला बंद भाव 4,694.50 डॉलर प्रति औंस था।

ईरान-अमेरिका युद्ध से परेशान एनआरआई भारत में खरीद रहे महंगे मकान

मुंबई, बेंगलूरु और एनसीआर में 1 से 5 करोड़ के अपार्टमेंट करा रहे बुक

नई दिल्ली ।

ईरान युद्ध के चलते प्रवासी भारतीय भारत में महंगे मकान खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनियों के मुताबिक करीब छह महीने से जारी ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में अनिश्चितता के बीच एनआरआई भारत में लक्जरी मकान खरीदने के लिए बातचीत बढ़ा रहे हैं। पूर्वकरा सीईओ ने कहा कि एनआरआई की दिलचस्पी बढ़ती दिख रही है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में हमारी प्री-सेल्स में एनआरआई की हिस्सेदारी 9 फीसदी थी, जो चौथी तिमाही में बढ़कर 13 फीसदी और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 15 फीसदी तक पहुंच गई है।

खास बात यह है कि एनआरआई की तरफ से आ रही मांग का करीब 87 फीसदी हिस्सा पश्चिम एशिया से है। उन्होंने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के छह देशों बहरिन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में रहने वाले एनआरआई ‘आज भारत को निवेश का स्थिर और लंबे समय का ठिकाना मान रहे हैं। इस साल 28 फरवरी को लड़ाई छिड़ने के बाद से जीसीसी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले होते रहे हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स और अधिकारियों का कहना है कि एनआरआई मुंबई, बेंगलूरु और एनसीआर में 1 से 5 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट बुक करा रहे हैं। लोढ़ा डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए कंपनी की अर्निंग्स कॉल के दौरान अनुमान लगाया कि यह रुझान पिछले साल से उलटा हो सकता है।

हालांकि विदेश में उथल-पुथल के कारण एनआरआई भारत में सुरक्षित ठिकाना तलाशेंगे। हमें उम्मीद है कि आत्रजन से जुड़ी वजहों से अमेरिका में रहने वाले खरीदार भी ऐसा ही करेंगे। पिछले साल भारत से करीब 35,000 करोड़ रुपए का निवेश दुबई के रियल एस्टेट में हुआ था।

बीमा सेक्टर में कमीशन से लेकर बेचने तक के बदल सकते हैं नियम, बदलाव की है तैयारी

बीमा सेक्टर में प्रीमियम तो बढ़ रहा है, लेकिन पॉलिसी की संख्या नहीं

नई दिल्ली, ।

लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। आईआरडीएआई की नजर अब बीमा कंपनियों के कमीशन, बैंकों के जरिए पॉलिसी बेचने के तरीके और ग्राहकों को सही पॉलिसी देने जैसे मुद्दों पर है। अगर ये बदलाव होते हैं तो इसका असर एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रोडेंटल लाइफ और एक्सिस मेक्स लाइफ जैसी कंपनियों पर पड़ सकता है। बीमा सेक्टर की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि प्रीमियम तो बढ़ रहा है, लेकिन पॉलिसी की संख्या नहीं।

बता दें वित्त वर्ष 2020 से

2025 के बीच नई पॉलिसी की संख्या हर साल औसतन 1.3 फीसदी घटी। वहीं नई पॉलिसी से मिलने वाला प्रीमियम करीब 8.9 फीसदी सालाना बढ़ा। इस दौरान कंपनियों का कमीशन खर्च भी करीब 14.5 फीसदी सालाना बढ़ा है यानी कंपनियों की ग्रोथ ज्यादा ग्राहक जोड़ने के बजाय महंगी पॉलिसी बेचने से आ रही है। वित्त वर्ष 2025 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने करीब 60,800 करोड़ रुपए कमीशन दिया। अब इस बात पर चर्चा है कि एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाले पैसे का तरीका बदला जाए। मतलब कमीशन का कुछ हिस्सा इस बात से जोड़ा जा सकता है कि ग्राहक

कितने समय तक पॉलिसी चालू रखता है। इससे सिर्फ पॉलिसी बेचने के बजाय उसे लंबे समय तक जारी रखने पर भी जोर बढ़ेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक 13वें महीने तक औसतन करीब 73.6 फीसदी पॉलिसी जारी रहती हैं। 37वें महीने तक यह आंकड़ा घटकर करीब 58.5 फीसदी रह जाता है यानी बड़ी संख्या में लोग कुछ साल बाद पॉलिसी छोड़ देते हैं। इसकी वजह महंगा प्रीमियम या ग्राहक की जरूरत के हिसाब से सही पॉलिसी नहीं मिलना हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के जरिए बीमा बेचने के नियमों में बदलाव हुआ तो

एसबीआई लाइफ पर ज्यादा नजर रहेगी। कंपनी के करीब 60 फीसदी एप्रील का सोत उसकी पैरेंट बैंक से जुड़ा है।

वहीं एचडीएफसी लाइफ और एक्सिस मेक्स लाइफ पहले से ऐसे मॉडल पर काम करती हैं, जहां पैरेंट बैंक दूसरी बीमा कंपनियों की पॉलिसी भी बेच सकता है। शुरुआत में नए नियमों से बीमा कंपनियों की बिज्ी पर कुछ दबाव पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से बेहतर पॉलिसी मिलने और पॉलिसी बीच में छोड़ने के मामले कम होने से इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है। फिलहाल ये बदलाव चर्चा में हैं।

विदेशी यात्रियों की आवाजाही प्रभावित होने के बाद भी भारत में होटलों ने की कमाई

घूमने-फिरने वाली जगहों के होटलों का प्रदर्शन बड़े कारोबारी शहरों के मुकाबले बेहतर रहा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण विदेशी यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई, फिर भी भारत में होटल की मांग मजबूत बनी रही। घूमने-फिरने, शादियों और बड़े कारोबारी कार्यक्रमों के लिए होटल की मांग ने सेक्टर को सहारा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में होटल सेक्टर की प्रति उपलब्ध कमरे से होने वाली कमाई करीब 10 फीसदी बढ़ी। कमरे का औसत किराया 6 फीसदी बढ़ा और कमरों की भराव दर करीब 2.33 फीसदी बढ़कर

65 फीसदी पहुंची यानी होटल कंपनियां ज्यादा कमरे चढ़ाने के साथ उनका किराया भी बढ़ाने में कामयाब रहीं। निवेशकों के लिए यही इस सेक्टर की सबसे अहम बात है।

रिपोर्ट के मुताबिक पहली तिमाही में मुंबई और घूमने-फिरने

वाली जगहों के होटलों का प्रदर्शन बड़े कारोबारी शहरों के मुकाबले बेहतर रहा। इसके पीछे घरेलू यात्रियों की बड़ी भूमिका रही। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा प्रभावित हुई और विदेशी पर्यटकों की संख्या पर दबाव पड़ा।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 183, निफ्टी 126 अंक गिरा



महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त रही, जबकि भारती एयरटेल, पावरग्रिड, इंफोसिस, एलएंडटी, नेस्ले इंडिया और श्रीराम फाइनेंस सबसे ज्यादा

गिरावट रही। वहीं इससे पहले आज सुबह शुरुआती घंटों में ही सेंसेक्स 240 अंक बढ़कर 77,900 के स्तर के करीब पहुंच गया जबकि निफ्टी 24,300 अंक ऊपर आया। दूसरी ओर एशिया-प्रशांत के ज्यादातर बाजार भी बढ़त पर रहे।

देश में चल रहे कई बड़े प्रोजेक्ट, मजदूरों की कमी से कई काम नहीं हो पा रहे पूरे

कंपनियों को हो रहा घाटा 10 फीसदी घटी कमाई, देरी से बढ़ रही प्रोजेक्ट की लागत,

नई दिल्ली, ।

देश में सड़क, रेलवे, मेट्रो, बिजली और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट पर काम जारी है। कंपनियों को नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं, लेकिन अब एक नई परेशानी सामने आ रही है। काम तो है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। इसका असर प्रोजेक्ट की रफ्तार से लेकर कंपनियों की कमाई पर पड़ने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में देश की 13 बड़ी लिस्टेड इंधा कंपनियों को मिले नए ऑर्डर पिछले साल के मुकाबले 63 फीसदी बढ़े, लेकिन इसके बावजूद इन कंपनियों की कुल आमदनी पिछले साल के आसपास ही रही और पिछली

तिमाही के मुकाबले 10 फीसदी घट गई।

रिपोर्ट के मुताबिक किसी कंपनी को 5,000 या 10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल जाना और उससे कमाई होना एक बात नहीं है। कंपनी की कमाई तब होती है, जब वह जमीन पर काम करती है। सड़क बनती है, पुल तैयार होता है या रेलवे से जुड़ा काम करती है। इसके लिए मशीनों और इंजीनियरों के साथ बड़ी संख्या में मजदूर चाहिए होते हैं। रिपोर्ट में बताया कि पहली तिमाही में राज्यों के चुनाव के कारण मजदूरों से जुड़ी परेशानी देखने को मिली। इसका असर काम की रफ्तार पर पड़ा यानी कंपनियों के पास ऑर्डर थे, लेकिन मजदूरों की कमी के कारण काम की रफ्तार धीमी रही।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

न्यूयार्क ।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गयी है। कीमतों में ये गिरावट वैश्विक आपूर्ति मार्ग होर्मुज पर तनाव में कमी से आई है। कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेज गिरावट दर्ज की गई। इससे अमेरिकी बेंचमार्क डब्ल्यूटीआई क्रूड 2 फीसदी ने फिसलकर 80 डॉलर प्रति बैरल के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब आ गया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी लगभग 2.25 फीसदी की गिरावट के साथ ही 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण विश्व के प्रमुख तेल आपूर्ति मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव कम होनो है जिससे जहाजों का आवागमन बेहतर हुआ है। ईरान और ओमान के बीच इस प्रमुख समुद्री मार्ग, डब्ल्यूटीआई क्रूड का अक्टूबर वनायद 2 डॉलर यानी 2.43 फीसदी गिरकर 80.36 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

देश में चल रहे कई बड़े प्रोजेक्ट, मजदूरों की कमी से कई काम नहीं हो पा रहे पूरे

कंपनियों को हो रहा घाटा 10 फीसदी घटी कमाई, देरी से बढ़ रही प्रोजेक्ट की लागत,

मजदूरों की कमी से कंपनियों के सामने एक और परेशानी खड़ी होती है। जब काम ज्यादा हो और मजदूर कम मिलें तो मजदुरी बढ़ जाती है यानी कंपनी को वही काम कराने के लिए पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर मजदूर समय पर नहीं मिलते तो प्रोजेक्ट पूरा होने में भी ज्यादा समय लगता है। इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ता है। हालांकि कंपनियों की कमजोर तिमाही के लिए सिर्फ मजदूरों की कमी जिम्मेदार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान युद्ध के कारण कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने भी कंपनियों का खर्च बढ़ाया है। इसके साथ मजदुरी की लागत भी बढ़ी है। नतीजा 13 कंपनियों का कामकाजी मुनाफे का

मार्जिन पिछले साल के मुकाबले करीब 1.10 फीसदी घटकर 10 फीसदी रह गया। वहीं शुद्ध मुनाफे से जुड़ा मार्जिन करीब 1.30 फीसदी घटकर 4 फीसदी रह गया है।

अगर मजदूरों की परेशानी लंबे समय तक रहती है तो इसका असर आम लोगों तक भी पहुंच सकता है। सड़क, पुल, रेलवे लाइन, मेट्रो या दूसरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में ज्यादा समय लग सकता है। काम लंबा खिंचा तो उसकी लागत भी बढ़ जाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि देश के सभी इंधा प्रोजेक्ट मजदूरों की कमी से अटक जाएंगे। अलग-अलग कंपनी, राज्य और प्रोजेक्ट पर इसका असर अलग हो सकता है।

रुपया बढ़त पर बंद



मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया 9 पैसे की बढ़त के साथ ही 95.31 पर बंद हुआ आज सुबह रुपया 95.40 पर खुला था। कच्चे तेल में आई गिरावट से भी रुपया मजबूत हुआ है। वहीं गत दिवस रुपया गिरावट पर बंद हुआ था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि सरकारी बैंकों के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लगातार हस्तक्षेप से रुपये की गिरावट को अधिक बढ़ने से रोकने में मदद मिली। इससे एशियाई शेयर बाजारों में कमजोरी और ईरान को लेकर फिर बढ़ी भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद रुपया सीमित दायरे में रहा।

जुलाई में मॉनसून सुधार से खरीफ बोआई सामान्य के करीब, घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत दिखी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून में सुधार होने से खरीफ बोआई को सामान्य के करीब लाने में मदद मिली। इससे कृषि क्षेत्र के लिए जोरिफिम आंशिक रूप से कम हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था ने वैश्विक जूनैतियों के प्रति काफी मजबूती दिखाई है, जिसका संकेत घरेलू मांग में उछाल और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों से मिलता है।मोडिया रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून जून में सुस्त रहने के बाद जुलाई में काफी सक्रिय दिखा। ऐसे में देश भर के जलाशयों का भंडारण एक दशक के औसत के करीब और पिछले अल नीनो वर्ष 2023 के स्तर से ऊपर रहा। जून के आखिर में बारिश की कमी कुल मिलाकर 38 फीसदी थी जो घटकर जुलाई के अंत तक 13 फीसदी रह गई है।हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि इस रिपोर्ट में बताई गई बातें लेखकों की निजी राय हैं और वे आरबीआई की राय को नहीं दर्शाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष खरीफ बोआई की अस्थायी प्रगति 2023 के मुकाबले बेहतर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगस्त से सितंबर के लिए देश भर में

मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में मॉनसून की गतिविधियों में सुधार होने से खरीफ फसलों के रकबे में सुधार हुआ। सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए खुले बाजार में बिज्ी योजना (ओएमएसएस) की भी घोषणा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन और ट्रैक्टर बिज्ी समेत कई संकेतकों से घरेलू मांग दमदार बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की वृहद आर्थिक बुनियादी स्थिति दमदार रहने से घरेलू अर्थव्यवस्था को सहारा मिली। पहली तिमाही में दिखी यह रफ्तार जुलाई में भी जारी रही। अधिकतर संकेतक विनिर्माण और सेवा गतिविधियों में तेजी की रफ्तार जारी रहे और वस्तुओं के निर्यात एवं आयात में दो अंकों की वृद्धि को दर्शाते हैं।रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में भी तेज वृद्धि हुई। इसे मुख्य तौर पर विनिर्माण में तेजी से रफ्तार मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य और पेय पदार्थों के कारण जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई लेकिन कीमती धातुओं को छोड़कर मुख्य मुद्रास्फीति मध्यम बनी रही।

राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे प्रदीप वर्मा, कहा- सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी है

बिभा संवाददाता

रांची। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा बुधवार को पहली बार पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर प्रदीप वर्मा ने सबसे पहले पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रदीप वर्मा को नई जिम्मेदारी के लिए



बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदीप वर्मा के अनुभव और नेतृत्व क्षमता से पार्टी को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिलना उनके संगठन के प्रति समर्पण और मेहनत का सम्मान है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। प्रदीप वर्मा ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, वह उनके लिए सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य फोकस संगठन के विस्तार और उसे मजबूत करने पर रहेगा। वह पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी

के साथ काम करेंगे। प्रदीप वर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, मुनेश्वर साहू, दीपक बंका, हेमंत दास, सूरज चौरसिया, अशोक बड़ाईक, केके गुप्ता, शोभा यादव, नीरज सिंह, सूरज शाहदेव, राहुल अवस्थी, रजनीश पांडे, रमेश सिंह, राकेश भास्कर, ललित ओझा, शशि भूषण भगत, पंकज सिन्हा, गोपाल सोनी, इंद्रजीत यादव सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।

भारतीय रेलवे का होगा कार्याकल्प: 7 प्रमुख हार्ड-डेंसिटी मार्गों को 4-लाइन करने का खाका तैयार

बिहान भारत

नई दिल्ली : केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सात उच्च-घनत्व (हार्ड-डेंसिटी) वाले प्रमुख रेलवे मार्गों को चार-लाइन (फोर-लाइन) में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना का खाका पेश किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप तैयार की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य रेलवे की क्षमता को बढ़ाना और भविष्य में यात्री तथा माल ढुलाई की बढ़ती जरूरतों को सुगमता से पूरा करना है। यह परियोजना भारतीय रेलवे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 11,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले ये सात मार्ग पूरे रेलवे नेटवर्क का मात्र 16 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद कुल रेल यातायात का लगभग 41 प्रतिशत भार वहन करते हैं। इस योजना के तहत देश के प्रमुख महानगरों और

क्षेत्रों को जोड़ने वाले दिल्ली-हावड़ा, हावड़ा-चेन्नई, चेन्नई-मुंबई, मुंबई-दिल्ली, दिल्ली-चेन्नई, मुंबई-हावड़ा और दिल्ली-गुवाहाटी मार्गों पर चार रेलवे लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने इस परियोजना के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि चार-लाइन होने से इन व्यस्त मार्गों पर ट्रेनों के आवागमन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे माल ढुलाई और यात्री परिवहन अधिक सुगम होगा, जिसके परिणामस्वरूप कुल परिवहन लागत में कमी आएगी। रेल मंत्री ने कहा कि यह विस्तार एक ऐसे आधुनिक रेलवे नेटवर्क का निर्माण करेगा जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ और टिकाऊ गतिशीलता (सस्टेनेबल मोबिलिटी) सुनिश्चित करेगा।

ईद-ए-मिलाद पर निकाला गया जुलूस

बिभा संवाददाता

देवघर। पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब की जयंति पर मनाया जाने वाला ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) का पर्व जिले में उत्साह और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की और एक-दूसरे को ईद-ए-मिलाद की बधाई दी। जिले के मधुपुर, साठ और पालोजोरी प्रखंड सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईद-ए-मिलाद के अवसर पर जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस दौरान पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब के जीवन, उनकी शिक्षाओं, दया, नेक कार्यों और ईंसानियत के संदेश को लोगों तक पहुंचाया गया। मौके पर मधुपुर में मंत्री हफिजुल हसन ने कहा कि ईद-ए-मिलाद का पर्व हमें एकता, भाईचारे और पवित्रता का संदेश देता है। सभी लोग मिल-



जुलुकर पर्व मनाते हैं और इस अवसर पर जरूरतमंदों की मदद करने एवं समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। वहीं विभिन्न जगह निकले गए जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। माइक के माध्यम से पैगंबर साहब के नेक कार्यों और ईंसानियत के प्रति उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाया गया। विभिन्न स्थानों पर जुलूस का रोक-रोककर स्वागत भी किया गया। इस दौरान हिन्दू-मुस्लिम सहित विभिन्न समुदायों के लोगों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द की मिसाल पेश की।

बीना स्टेशन पर एनआई कार्य से छह ट्रेनों के मार्ग में बदलाव

प्रयागराज(बिभा)। झांसी के बीना स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य के चलते रेलवे ने कुछ ट्रेनों के मार्ग में संशोधन किया है। यह जानकारी बुधवार को उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से जारी संशोधित सूचना के अनुसार गोरखपुर-ओखा, ओखा-गोरखपुर, सूरत-मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर-सूरत, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बलिया और बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के मार्ग बदले गए हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले संशोधित मार्ग की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। रेल प्रशासन के अनुसार बीना-आगासौद के बीच तीसरी रेल लाइन को जोड़ने के लिए यार्ड रीमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इसके कारण कुछ ट्रेनों को निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा।

इन ट्रेनों के मार्ग बदले : 15045 गोरखपुर-ओखा एक्सप्रेस 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ग्वालियर-शिवपुरी-गुना होकर चलेगी। इस दौरान चार फेरे होंगे। 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक गुना-शिवपुरी-ग्वालियर मार्ग से संचालित होगी। इसके चार फेरे होंगे। 19053 सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 18 सितंबर से 9 अक्टूबर तक गुना-शिवपुरी-ग्वालियर होकर चलेगी। इसके चार फेरे होंगे। 19054 मुजफ्फरपुर-सूरत एक्सप्रेस 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक ग्वालियर-शिवपुरी-गुना मार्ग से चलेगी। इसके चार फेरे होंगे। 11071 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बलिया एक्सप्रेस 7 से 14 अक्टूबर तक संशोधित मार्ग से चलेगी। अब यह इटारसी-जबलपुर-कटनी होकर संचालित होगी। इसके आठ फेरे होंगे। 11072 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 7 से 14 अक्टूबर तक कटनी-जबलपुर-इटारसी मार्ग से चलेगी। इसके आठ फेरे होंगे। जनसंपर्क अधिकारी अमित ने बताया कि अधोसंरचना को बेहतर बनाने के लिए बीना स्टेशन पर यह महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के संशोधित मार्ग की सूचना जारी की गई है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि संबंधित मार्गों में यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन के मार्ग और परिवालन की नवीनतम जानकारी अवश्य जांच लें। उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन को होने वाली असुविधा के लिए खेद है और यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा करता है।

अगासोद स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग से मुरादाबाद रेल मंडल की तीन ट्रेनें होंगी प्रभावित

मुरादाबाद(बिभा)। यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण 24 अक्टूबर तक अलग-अलग तिथियों में नॉन इंटरलॉकिंग में ब्लॉक के कारण मुरादाबाद मंडल में संचालित तीन रेलगाड़ियां प्रभावित होंगी। जिसमें दो ट्रेनें निरस्त एवं एक परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मण्डल में वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक महेश यादव ने बताया कि अगासोद स्टेशन पर झांसी मंडल के अंतर्गत बीना वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलखंड में अगासोद बीना के मध्य तीसरी रेल लाइन के लिए यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण 24 अक्टूबर तक अलग-अलग तिथियों में नॉन इंटरलॉकिंग में ब्लॉक के कारण मुरादाबाद मंडल में संचालित तीन रेलगाड़ियां प्रभावित होंगी। जिसमें दो ट्रेनें निरस्त एवं एक परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। रेलगाड़ी संख्या 05073 साप्ताहिक गाड़ी 29 सितम्बर, 6 अक्टूबर एवं 13 अक्टूबर को निरस्त रहेंगी। रेलगाड़ी संख्या 05074 साप्ताहिक गाड़ी 26 सितम्बर, 3 अक्टूबर एवं 10 अक्टूबर को निरस्त रहेंगी। इसके अलावा रेलगाड़ी संख्या 18477 पुरी-योगनगरी ऋषिकेश 7 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग द्वारा संचालित की जाएगी।

अनुकृति गुसाई रावत बर्नी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, समीर बाजपेई ने दी बधाई

देहरादून(बिभा)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू तथा 40-लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी अनुकृति गुसाई रावत को भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर किला मजदूर यूनियन, आर्डीनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर के महामंत्री समीर बाजपेई ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं कार्यालय प्रभारी कुंदन परिहार द्वारा 25 अगस्त 2026 को जारी प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची में अनुकृति गुसाई रावत को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। समीर बाजपेई ने कहा कि यह जिम्मेदारी उनके नेतृत्व, सक्रियता और जनसेवा के प्रति समर्पण का सम्मान है। उन्होंने विश्वास जताया कि वे पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के साथ संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। समीर बाजपेई ने आगामी 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अनुकृति गुसाई रावत के विधायक निर्वाचित होने की शुभेच्छा व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि पार्टी नेतृत्व उन्हें विधानसभा चुनाव में अवसर देगा और वे जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगी।



बिभा संवाददाता

रांची। जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के नेतृत्व में भर्ती व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हित में चल रही भर्ती सुधार यात्रा बुधवार को तीसरे दिन चतरा और कोडरमा होते हुए गिरिडीह पहुंची। इस अवसर पर यात्रा का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड की युवा पीढ़ी के साथ धोखा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं के भविष्य के सख्त खिलवाड़ किया और राज्य के मानव संसाधन को उचित



सम्मान नहीं दिया। देवेंद्र महतो ने कहा कि छात्रों के भविष्य की गारंटी और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भर्ती सुधार यात्रा के माध्यम से पूरे झारखंड में युवाओं और अभ्यर्थियों को संगठित किया जाएगा। यात्रा की

शुरूआत रामगढ़ के नेमरा से हुई है। गुरुवार को यात्रा देवघर पहुंचीगी। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर जन-जागरण, पदयात्रा और जनसभाओं के माध्यम से युवाओं एवं अभ्यर्थियों को भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए जागरूक किया गया। यात्रा की शुरूआत चतरा

एमएमडीआर संशोधन बिल झारखंड के खनिज अधिकार और राजस्व पर हमला : कमलेश

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के एमएमडीआर संशोधन बिल के समर्थन में दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर राज्य के संवैधानिक और वित्तीय अधिकार को कमजोर करने वाले कानून को राज्यहित में बताया जनता को गुमराह करने की कोशिश है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि रघुवर दास को पहले यह बताना चाहिए कि उनके शासनकाल में झारखंड की खनिज संपदा से राज्य और जनता को कितना वास्तविक लाभ मिला। साथ ही, यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि खनन प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में अपेक्षित बदलाव क्यों नहीं आया।

उन्होंने कहा कि भाजपा को यदि झारखंड की खनिज संपदा से वास्तव में इतनी ही चिंता है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि एमएमडीआर संशोधन के बाद राज्यों के अधिकार, खनिज-युक्त भूमि उपकरण और खनिज राजस्व की सुरक्षा की ठोस गारंटी क्या है। केवल यह कहना कि 90 प्रतिशत भुगतान राज्यों को मिलता है, वास्तविक सवाल का जवाब नहीं है। असली सवाल यह है कि केंद्र सरकार कानून बनाकर राज्यों के राजस्व अधिकार और नीति-निर्धारण की क्षमता को सीमित क्यों करना चाहती है। केशव महतो कमलेश ने रघुवर दास के पारदर्शी लीगल माइनिंग के दावे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि रघुवर दास को अपने कार्यकाल का भी आकलन करना चाहिए और बताया चाहिए कि उस दौरान खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों

के हित में क्या ठोस कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा न तो भाजपा की निजी संपत्ति है और न ही केंद्र सरकार की। यह झारखंड की जनता, आदिवासियों और मूलवासियों की प्राकृतिक संपदा है। इसके दोहन से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल राज्य के विकास और आम लोगों के कल्याण में होना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खनन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास पर खर्च किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ऐसा हो, जिससे उसका वास्तविक लाभ राज्य और यहां की जनता को मिले, न कि उनके अधिकार और राजस्व हित कमजोर हो।

रील्स से ज्यादा कीमती है जिंदगी: रेलवे ट्रेक पर स्टंट और अतिक्रमण के खिलाफ पूर्व रेलवे की बड़ी कार्रवाई पूर्व रेलवे ने 3 महीने में 853 लोगों को भेजा जेल

बिहान भारत

कोलकाता: सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और रील्स बनाने के चक्कर में लोग अक्सर अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। इस खतरनाक प्रवृत्ति और रेलवे पटरियों को अनधिकृत रूप से पार करने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए, पूर्व रेलवे ने कड़ा रुख अपनाया है। महाप्रबंधक सुश्री गीतिका पांडेय के नेतृत्व में पूर्व रेलवे लगातार जन-जागरूकता अभियान चलाकर यह संदेश दे रहा है कि रेलवे ट्रैक केवल ट्रेनों के परिचालन के लिए हैं, न कि पैदल चलने, शॉर्टकट मारने या वीडियोघ्राफ़ी करने के लिए। सुरक्षित आवागमन के लिए फुट ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज जैसी सुविधाओं को मौजूद होने के बावजूद लोग शॉर्टकट अपनाकर हादसों को दावत दे रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे ने अब सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।



महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री अमिया नंदन सिन्हा के स्पष्ट निर्देशों के बाद, रेलवे सुरक्षा बलों ने 1 मई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक सभी मंडलों में रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत सघन प्रवर्तन अभियान चलाया। इन तीन महीनों के दौरान पूर्व रेलवे के चार मंडलों में कुल 828 अभियोजन मामले दर्ज किए गए और 853 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, 6,608 मामलों में कार्रवाई करते हुए अदालत के माध्यम से 3,18,220 रुपये का जुर्माना तथा 33,12,900

रुपये की पेनाल्टी वसूली गई। विभिन्न मंडलों में की गई इस कार्रवाई के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि रेलवे इस मुद्दे पर पूरी तरह से सतर्क और मुसैद है। आसन्न मामले में 152 अभियोजन मामले दर्ज कर 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया और भारी जुर्माना वसूला गया। वहीं, हावड़ा मंडल में 97 लोगों की गिरफ्तारी के साथ सबसे अधिक 3,468 जुर्माना मामले दर्ज हुए, जिनसे लाखों रुपये की पेनाल्टी प्राप्त हुई। मालदा टाउन और सियालदह मंडल में भी रेलवे ने सख्ती दिखाते हुए क्रमशः

300-300 लोगों को गिरफ्तार किया और जुर्माने के रूप में बड़ी राशि वसूली की। पूर्व रेलवे के अधिकारियों का स्पष्ट मानना ​​है कि यह प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा, लेकिन केवल कानूनी कार्रवाई से समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता; इसके लिए आम जनता में आत्म-जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार का होना सबसे अहम है। इस पूरे अभियान के संदर्भ में पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शिवराम माझि ने आम जनता से भावुक और सख्त अपील करते हुए कहा कि कोई भी सोशल मीडिया वीडियो या शॉर्टकट अपनी जान जोखिम में डालने के लायक नहीं है। उन्होंने यात्रियों से अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और केवल निर्धारित पुलों व सुरक्षित क्रॉसिंग का ही उपयोग करने का विशेष आग्रह किया है।

मुरादाबाद स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान में 1.50 लाख का राजस्व अर्जित



मुरादाबाद। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए बुधवार को चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान कुल 27 रेलगाड़ियों में जांच की गई, जिसमें 237 मामलों में 1,50,735 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। अभियान के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव की उपस्थिति में सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक हरि सिंह मीना, मुख्य टिकट निरीक्षक भावेश

शर्मा, 24 टिकट चेकिंग स्टाफ एवं 09 रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ ने संयुक्त रूप से सघन टिकट जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना टिकट यात्रा के 122 मामले पकड़े गए, जिनसे 81,060 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। अनियमित यात्रा के 93 मामलों में 63,175 रुपये तथा गंदगी फैलाने के 22 मामलों में 6,500 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।